सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 45, नई दिल्ली । शनिवार, 27 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते।

03 डीयू में 25 अप्रैल से शुरू होगी PG के लिए दाखिले की दौड़....
06 तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाने का अरविंद केजरीवाल का दावा हुआ फुस्स!
08 बिजेंद्र दल की बरिस्ट नेता श्री नगेंद्र प्रधान कोंग्रेस मे शामिल

बैटरी रिक्शा मामले में राज्य सरकार से मांगा उच्च न्यायालय ने जवाब

संजय बाटला

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शहरों में बिना नियम के चल रहे हजारों बैटरी रिक्शा के संदर्भ में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है इतनी बड़ी संख्या में शहरों में दौड़ रहे बैटरी रिक्शा के लिए क्या कोई गाइडलाइन है। **इनके कारण लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।** यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मेरठ के मनोज कुमार चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है। **मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई नियत की गई है।** जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट सौरभ सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के प्रत्येक शहर में हजारों गैर रजिस्टर्ड बैटरी रिक्शा दौड़ रहे हैं। खास बात यह कि इनकी न तो कोई गाइडलाइन है और न ही रूट निर्धारित हैं। इस कारण यह बेतरतीब तरीके से कहीं भी धड़ल्ले से चल रहे हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम व वहां की सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण भी हैं। **क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का आने वाला फैसले को भी वहा का परिवहन विभाग दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की तरह हवा में उड़ा देगा या जनहित पर उस पर सही कार्यवाही करेगा, बड़ा सवाल? क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग की दृष्टि में ना तो जनता की सुरक्षा की कोई अहमियत है और ना उच्च न्यायालय के आदेश और उपराज्यपाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन की** दिल्ली परिवहन विभाग में अहमियत है तो सिर्फ आला अधिकारी की सोच और उसके द्वारा ज़ारी (चाहे उस आदेश से नियमो की अवहेलना हो या सुरक्षा में) आदेशों और दिशा निर्देशों की।

बिना वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस अब आप भी चला सकते है सड़को पर वाहन, और वह भी बिना डर, जाने पूरा विवरण

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जब से भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता खत्म कर दी है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। वाहन नियम के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाने पर 5000 तक का चालान काटा जा सकता है। अगर आप इस दौरान ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हैं तो आपको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जुर्माना या जेल भी हो सकती है। पर अब **सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के नियमों के अनुसार, जिस भी इलेक्ट्रिक वाहन की अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा है, उस के लिए इन वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए किसी भी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।** अगर आपके पास भी अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और ना ही चालान का डर।

नरेला थाने से सटा डीटीसी बस शैड कभी भी यात्रियों पर गिर सकता है

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एसडी सेठी। उत्तरी बाहरी दिल्ली के नरेला पुलिस स्टेशन से सटे डीटीसी बस स्टैंड का शैड पूरी तरीके से जर्जर हालत में झुक चुका है। जंक खाए बस शैड की हालत इतनी जर्जर है, कि वह बस की इंतजार कर रहे लोगों को धूप और गर्मी, बरसात से राहत देने की बजाए उनकी जान जोखिम में जरूर डाल सकता है।हादसे को न्योता देते इस बस शैड को रिपेयर या नया शैड लगाने पर तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए।इस बाबत फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिन्दर सिंह दहिया का कहना है कि नरेला ग्रामीण क्षेत्र के तमाम बस स्टैंड शैडो की हालत बेहद खराब है। इन खतरनाक जर्जर बस स्टैंड शैड के नीचे दबने से कभी भी बडा हादसा हो सकता है।

फेडरेशन के अध्यक्ष का दावा है कि डीटीसी की संपति की बावत अधिकारियों की लापरवाही का यह आलम है कि बस शैड लगने के बाद एक बार भी पलट कर नहीं देखा है। बस शैडो की मेंटेनेंस या रख रखाव तो कभी हुआ ही नही। इस वक्त नरेला क्षेत्र के तमाम डीटीसी बस शैडो की हालत बेहद खराब है। जंक खाए जर्जर बस स्टैंड शैड से कभी भी जान और माल का नुकसान हो सकता है।

फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिन्दर सिंह दहिया ने डीटीसी के आला अधिकारियों को चेताया है कि समय सीमा के भीतर नरेला क्षेत्र के तमाम बस स्टैंड शैड को तत्काल दुरूस्त किया जाए या बस की इंतजार करने वालों को बैठने की व्यवस्था के तहत नए बस स्टैंड शैड को लगाया जाए।

साहिबाबाद में ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन पर बनेगा बस अड्डा

गाजियाबाद। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किए जा रहे पुराने बस अड्डे को अगले 15 दिन में खाली कर दिया जाएगा। अस्थायी रूप से बस अड्डे को साहिबाबाद में ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन की जमीन पर स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, मेरठ, बुलंदशहर के लिए संचालित होने वाली बसें पुराना बस अड्डे से ही अपने निर्धारित समय पर होकर गुजरेंगी।

गाजियाबाद पुराना बस अड्डा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। इसमें करीब 100 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। इसका काम ओमेक्स कंपनी को दिया गया है। प्रारंभिक कार्य कंपनी ने शुरू भी कर दिया है। कंपनी की ओर से परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डे को खाली करने के लिए लगातार पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन एक साल में भी निगम को अस्थायी बस अड्डा बनाने के लिए जमीन नहीं मिल सकी। एआरएम निर्मल वर्मा ने बताया कि बस अड्डे के लिए सिद्धार्थ विहार में भी जमीन देखी गई थी, लेकिन अब साहिबाबाद ई-बसों के चार्जिंग स्टेशन पर बस अड्डे को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। अगले दो सप्ताह में बस अड्डे को खाली कर कार्यदायी संस्था को सौंप दिया जाएगा। मेरठ-बुलंदशहर से आने जाने वाली बसें पुराना बस अड्डे से होकर गुजरेंगी। ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। करीब दो साल में बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

हरियाणा में भीषण हादसा: खड़े कंटेनर से टकराया श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो, दो बच्चियों सहित तीन की मौत, 23 घायल

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात करीब साढ़े 11 बजे छोटा हाथी टेंपो में सवार होकर 26 श्रद्धालु वृंदावन दर्शन कर जालंधर पंजाब लौट रहे थे।

हरियाणा के तावडू जिले की सीमा से गुजर रहे केएमपी मार्ग पर गुरुवार-शुक्रवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां गांव पढेनी और धुलावट टोल प्लाजा के समीप बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े कंटेनर में श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो जा टकराया। इस भीषण हादसे में में एक नौ वर्षीय बच्ची और महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक पांच वर्षीय बच्ची ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायलों को तावडू, रेवाड़ी, नल्हड़ सहित रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात करीब साढ़े 11 बजे छोटा हाथी टेंपो में सवार होकर 26 श्रद्धालु वृंदावन दर्शन कर जालंधर पंजाब लौट रहे थे। टेम्पो में भोगपुर जालंधर के रहने वाले प्रीति पत्नी राहुल 23 वर्ष, सुखी पुत्र पहलाद 19 वर्ष, अमायरा पुत्र राहुल चार वर्ष, पूनम पत्नी राजेश 24 वर्ष, राजेश पुत्र बनवारी 26 वर्ष, अरमान पुत्र राजेश 5 वर्ष, मन्नत पुत्री राजेश तीन वर्ष, मनप्रीत पुत्री राहुल पांच वर्ष और गांव टीना जालंधर के रहने वाले विक्की पुत्र पहलाद 30 वर्ष, पूजा पत्नी विक्की 28 वर्ष, कोमल पुत्री विकी पांच वर्ष, साहिल पुत्र विक्की छह वर्ष, प्रहलाद पुत्र भोभल 55 वर्ष, बीना पत्नी प्रहलाद 53 वर्ष, राजेश पुत्र बनवारी 26 वर्ष, विकास पुत्र विक्की दो वर्ष, दीपू पुत्र कल्ली सात वर्ष और नौ लोग बोरखेड़ा जिला डीग राजस्थान सहित पहाड़ी के रहने वाले कुल 26 लोग सवार थे। टेंपो विक्की चल रहा था।

जैसे ही टेम्पो धुलावट के टोल प्लाजा से थोड़ा आगे पहुंचा तो सामने मार्ग पर बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े कंटेनर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। दो की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही केएमपी ट्रैफिक थाना और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

तावडू सदर थाना प्रभारी जितेंद्र ने बताया कि इस हादसे में तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। मृतकों में बीना पत्नी प्रहलाद (45 वर्ष), रितिका पुत्री कल्लू उर्फ गोविंदा (9 वर्ष) गांव टीना जिला जालंधर और मनप्रीत पुत्री राहुल (पांच वर्ष) भोगपुर जालंधर पंजाब के रूप में हुई।

सदर थाना तावडू प्रभारी जितेंद्र ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत इस मामले को लेकर नहीं मिली है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दो बच्चियों सहित महिला के शव सीएससी नूंह के शव ग्रह में रखवा दिए गए हैं।

संस्कारशाला - "स्पर्श चिकित्सा की उपचार शक्ति: स्पर्श की खोई हुई कला को फिर से खोजना" : डॉ अंकुर शरण

आज की दुनिया की आपाधापी में, स्क्रीन और डिजिटल विकर्षणों के बीच, ऐसा लगता है कि हम एक साधारण स्पर्श - स्पर्श चिकित्सा - के गहरे प्रभाव को भूल गए हैं। माँ के हाथ के कोमल स्पर्श से लेकर पिता की आश्वस्त थपथपाहट तक, जुड़ाव के इन क्षणों में उत्थान, उपचार और कायाकल्प करने की शक्ति है।

इसे चित्रित करें: एक माँ धीरे से अपने बच्चे के माथे पर अपना हाथ रखती है, चिंताओं को दूर करती है और उन्हें शांतिपूर्ण नींद में सुलाती है। या एक पिता, मजबूत लेकिन आरामदायक पकड़ के साथ, अपने बच्चे की पीठ पर आश्वस्त थपथपाकर उसका उत्साह बढ़ाता है। ये इशारे, जो एक समय आम थे, अब हमारे तेज़ गति वाले जीवन में दुर्लभ खजाने हैं।

संस्कृत में, 'स्पर्श' का अर्थ है स्पर्श, और 'चिकित्सा' का अर्थ है थेरेपी या उपचार। स्पर्श चिकित्सा स्पर्श के माध्यम से मानवीय संबंध के सार को समाहित करती है - एक सार्वभौमिक भाषा जो भाषा, संस्कृति और समय की बाधाओं को पार करती है। यह आराम, प्रोत्साहन और प्यार की भाषा है।

आज की दुनिया में, जहां आभासी बातचीत अक्सर आमने-सामने की मुठभेड़ों की जगह ले लेती है, स्पर्श के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। शोध से पता चला है कि शारीरिक स्पर्श से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हार्मोन बंधन और तनाव को कम करने के लिए जिम्मेदार है। यह विश्वास, सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है।

फिर भी, इसके गहरे प्रभावों के बावजूद, स्पर्श चिकित्सा लगातार दुर्लभ होती जा रही है। हाथ मिलाना, जो कभी अभिवादन करने और संबंध स्थापित करने का एक सामान्य तरीका था, उसकी जगह दूर से सिर हिलाकर या आभासी तरंगों ने ले ली है। मानवीय स्पर्श की गर्माहट की जगह धीरे-धीरे स्क्रीन की ठंडक ले रही है।

लेकिन हमारे जीवन में स्पर्श की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में अभी देर नहीं हुई है। हम स्पर्श चिकित्सा के महत्व के बारे में बातचीत शुरू करके और इसे अपनी दैनिक बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल करके शुरुआत कर सकते हैं। एक साधारण हाथ मिलाना सम्मान, विश्वास और खुलेपन को व्यक्त कर सकता है - बाधाओं पर काबू पाने और सार्थक संबंध बनाने के लिए आवश्यक गुण।

इसके अलावा, स्पर्श चिकित्सा के लिए भव्य इशारों या विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती है। यह पीठ थपथपाने, गले लगाने या कंधे पर हाथ रखने जितना सरल हो सकता है। दयालुता के इन छोटे कार्यों में आत्माओं को ऊपर उठाने, आत्मविश्वास पैदा करने और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाने की क्षमता है।

तो आइए अपने जीवन में स्पर्श चिकित्सा को पुनर्जीवित करने के लिए एक सचेत प्रयास करें। आइए एक कोमल स्पर्श या दृढ़ता से हाथ मिलाने की शक्ति को कम न समझें। शोर और अराजकता से भरी दुनिया में, आइए मानवीय संबंध के उपचारात्मक बाम को अपनाएं - एक समय में एक स्पर्श।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सीड्स को डाइट में शामिल करने से शरीर को मिलते हैं कई फायदे, न करें ऐसी गलतियां

हम सभी अपनी डाइट में तरह-तरह की फलों व सब्जियों को शामिल करते हैं। लेकिन नट्स और सीड्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि यह भी हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

स्वस्थ रहने के लिए डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। हम सभी अपनी डाइट में तरह-तरह की फलों व सब्जियों को शामिल करते हैं। लेकिन नट्स और सीड्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि यह भी हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। खासतौर पर नट्स, जिन्हें हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं।

जबकि सीड्स में हेल्दी फैट्स, कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड आदि जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे- चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो वहीं अलसी के बीच में फाइबर और लिगनेन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

इसी तरह कद्दू का बीज जिंक और मैग्नीशियम का बढ़िया स्त्रोत माना गया है। जब लोग सीड्स खाते हैं, तो इसका गलत तरीके से सेवन करते हैं। इसलिए उन्हें फायदे की जगह नुकसान होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीड्स का सेवन करने के दौरान किन छोटी-छोटी गलतियों को करने से बचना चाहिए।

जरूरत से ज्यादा सेवन करने के नुकसान

हांलाकि इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सीड्स हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वहीं इसके सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। सीड्स कैलोरी से भरपूर होते हैं। ऐसे में अगर आप सीड्स खाने के दौरान उसकी मात्रा का ध्यान न रखा जाए, तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी का सेवन कर लेते हैं। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए आप दिनभर में एक से दो चम्मच सीड्स का सेवन करें।

कई तरह से करें सीड्स का सेवन

हमारी सेहत के लिए सीड्स काफी अच्छे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सीड्स में अलग-अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है अलग-अलग तरह के सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। आप सूरजमुखी से लेकर कद्दू तक के बीजों का सेवन कर सकते हैं। जब एक ही तरह से सीड्स का सेवन करते हैं, तो कई अन्य जरूरी पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं।

गलत तरीके से सेवन

सीड्स स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। लेकिन इसके सेवन का एक सही तरीका होता है। लेकिन जब आप गलत तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अलसी के बीज को पीसकर खाना चाहिए। बता दें कि अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। वहीं साबुत अलसी को पचाने में शरीर को कठिनाई होती है। वहीं इनको पीसकर खाने से इन्हें पचाना आसान होता है। साथ ही यह बेहतर तरीके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक इसी तरह से जब आप चिया सीड्स का सेवन करते हैं। तो उनको खाने से पहले भिगो लें। जिससे कि चिया सीड्स की कंसिस्टेंसी जेल जैसे बन जाए और आप उनको न सिर्फ बेहतर तरीके से खा सकें, बल्कि शरीर इसे अच्छे से पचा सके।

प्रोसेस्ड बीज चुनें

आज के समय में सीड्स को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मार्केट में रोस्टेड या सॉल्टेड वैरायटीज में प्रोसेस्ड सीड्स मिल जाते हैं। वहीं लोग भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। हांलाकि इसमें एक्स्ट्रा शुगर, ऑयल व नमक हो सकता है। जिससे आपके स्वास्थ्य को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए आप कच्चे या फिर कम प्रोसेस्ड सीड्स चुनें।

18 साल की चीनी महिला को हुई 'लव ब्रेन' की बीमारी, एक दिन में अपने बॉयफ्रेंड को 100 से ज्यादा बार किया

18 वर्षीय चीनी महिला को उसके प्रेमी की शिकायत के बाद उसके घर आने के बाद डॉक्टरों के पास ले जाया गया और 'लव ब्रेन' का रोग पाया गया। महिला के ₹लव ब्रेन₹ से पीड़ित होने का पता चलने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर डॉयिन को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया है। एक ने यहां तक पूछा, ₹क्या वह सिर्फ एक नियंत्रण सनकी नहीं है?

चीन में एक महिला को अपने प्रेमी को बार-बार फोन करने के बाद 'लव ब्रेन' का पता चला, जिसमें एक दिन ऐसा भी था जब उसने उसे 100 से अधिक बार फोन किया था। रिपोर्टों के अनुसार, 18 वर्षीय महिला अपने साथी से उसके ठिकाने के बारे में लगातार पूछती रहती थी और उसे "हर समय उसके आसपास रहने की ज़रूरत होती थी"।

लव ब्रेन क्या है?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के अनुसार, महिला ज़ियाओयू को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चला था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'लव ब्रेन' कहा जाता है। चेंग्दू के द फोर्थ पीपुल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर और ज़ियाओयू का इलाज करने वाले व्यक्ति डूना ने कहा कि ₹यह स्थिति चिंता, अवसाद और द्विध्रुवी विकार जैसी अन्य मानसिक बीमारियों के साथ भी मौजूद हो सकती हैर।

एससीएमपी की रिपोर्ट के अनुसार, जियाओयू विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए अपने घर से बाहर चली गई, जहां उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हुई। वे जल्द ही घनिष्ठ हो गए, लेकिन यह सब तब बदल गया जब आदमी "असुविधाजनक और दबा हुआ" महसूस करने लगा।

रिपोर्टों के अनुसार, ज़ियाओयू ने अपने प्रेमी से "लगातार ध्यानर की मांग की और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई। वह यह भी चाहती थी कि ₹वह दिन और रात के सभी घंटों में उसके संदेशों का जवाब दे।"

एससीएमपी ने बताया कि जियाओयू का व्यवहार तब सामने आया जब उसका एक वीडियो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। क्लिप में, वह अपने प्रेमी को अपना वीचैट कैमरा चालू करने के लिए संदेश भेजती है और उसे बार-बार कॉल करती है।

आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, जिस दिन उसने उसे 100 से अधिक बार फोन किया, उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने अपने घर के आसपास की चीजों को भी तोड़ दिया। दूसरी ओर, प्रेमी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ज़ियाओयू के घर पहुंची, तो उसने कथित तौर पर बालकनी से कूदने की धमकी दी।

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उसकी स्थिति को ₹लव ब्रेन₹ कहा जा रहा था। डॉयिन पर एक यूजर ने लिखा, "क्या वह सिर्फ एक नियंत्रण सनकी नहीं है?" एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पास प्रेम मस्तिष्क है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरह व्यवहार करता हूं,"।

धूप के कारण झुलस गई है त्वचा तो इस तरह से करें देखभाल, फॉलो करें ये 10 आसान घरेलू उपाय

गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। धूप की वजह से अगर त्वचा झुलस गई है, तो इस समस्या को कम करने के लिए आप घर के किचन में उपलब्ध इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। नआज हम आपको इस लेख में 10 आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो आपकी सनबर्न की समस्या में राहत देंगी।

समर सीजन आ चुका है, इस मौसम में अक्सर चेहरे पर सनबर्न के कारण दाग-धब्बे पड़ जाते हैं। जो कि यह चेहरे की खूबसूरती को प्रभावित करता है। आमतौर पर गर्मियों में सनबर्न की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य की तेज किरणें त्वचा को झुलसा देती हैं। इससे आपकी स्किव खराब हो जाती है। सनबर्न को रिमूव करना आसान नहीं होता। आज हम आपको इस लेख में 10 आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो आपकी सनबर्न की समस्या में राहत देंगी।

सनबर्न रिमूव करने के 10 घरेलू नुस्खे

- सबसे पहले आप गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें, इससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहे और उसमें रुखापन न आए। आप पानी के साथ-साथ, जलजीरा, आमपना, शिकंजी आदि का सेवन करें।

- त्वचा को अंदरुनी और बाहर दोनों ही तरफ से आपको हाइड्रेटेड रखना चाहिए। इसके लिए आप एलोवेरा जेल, कोकोनट वॉटर, गुलाब जल आदि को टोनर की तरह चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज्ड रहती है।

- त्वचा पर मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस लेप में शहद भी मिक्स कर सकते हैं। ऑयली त्वचा वालों को मुल्तानी मिट्टी के साथ गुलाब जल मिक्स करना चाहिए।

- गर्मियों में आप दही और बेसन का स्क्रब भी चेहरे पर लगा सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर हैं और त्वचा की डेड स्किन को रिमूव करने की क्षमता को रखता है।

- आप चेहरे पर खीरे का रस भी लगा सकते हैं। इससे विटामिन-सी होते है, जो त्वचा के दाग-धब्बों को कम करता है और स्किन को गहराई तक साफ करता है। खीरे का रस लगाने से त्वचा को ठंडक और ताजगी भी आती है।

- आप घर में आइस फेशियल भी कर सकती हैं। इससे भी आपको सनबर्न की समस्या में आराम मिलेगा और त्वचा के रोम छिद्रों का आकार भी छोटा होगा, जिससे त्वचा में कसाव आएगा।

- सनबर्न को रिमूव करने के लिए आप टमाटर का टुकड़ा लेकर चेहरे पर धीरे-धीरे रब करें। इससे टैनिंग दूर होती है और त्वचा में ग्लो आता है।

- आप पानी में फिटकारी डालकर उस पानी से चेहरे को साफ करें। ध्यान रखें कि फिटकरी के घोल में साधारण पानी मिलाने के बाद ही आप चेहरे को वॉश करें। इससे भी सनबर्न की समस्या दूर होगी।

- आप पपीते का फेस पैक बनाकर लगाएं। ऐसा नियमित करने पर आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप पपीते के साथ दही मिक्स करके फेस पैक बना सकती है।

हर्ट को स्वस्थ रखने के लिए हाइपरटेंशन से दूर रहें, स्ट्रोक का खतरा कम होगा

ऑफिस की तंग समय-सीमाओं और हमारी खराब लाइफस्टाइल के कारण तनाव हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि थोड़ी मात्रा में तनाव होना कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लंबे समय तक तनाव हमारे समग्र स्वास्थ्य, विशेष रूप से हृदय प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है।

हर्ट पर लॉन्ग टर्म तनाव का प्रभाव

डॉक्टर के मुताबिक, क्रोनिक तनाव शरीर में शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक समूह शुरू करता है, जिसमें कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे तनाव हार्मोन की रिहाई भी शामिल है। उनका कहना है कि ये हार्मोन रक्तचाप बढ़ा सकते हैं, हृदय गति बढ़ा सकते हैं और धमनियों में सूजन पैदा कर सकते हैं।

समय के साथ, इस लगातार तनाव प्रतिक्रिया से रक्त वाहिकाओं को नुकसान हो सकता है, जिससे उनमें प्लाक बनने और संकुचन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कोरोनरी धमनी रोग की एक पहचान है। इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक तनाव उच्च रक्तचाप के विकास में योगदान कर सकता है, जो हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। इसके अलावा, लंबे समय तक तनाव में रहने से दिल की विफलता का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय के साथ हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है।

क्रोनिक तनाव और हृदय संबंधी जोखिम को कैसे कम करें

तनाव प्रबंधन तकनीकों का पालन करें

तनाव कम करने वाली एक्टिविटीज जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग, या प्रगतिशील मांसपेशी छूट को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। ये तकनीकें तनाव के शारीरिक प्रभावों को कम करके मन और शरीर को शांत करने में मदद कर सकती हैं।

नियमित रूप से व्यायाम करें

नियमित शारीरिक गतिविधि में लिप्त रहें, क्योंकि व्यायाम न केवल हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि प्राकृतिक तनाव निवारक के रूप में भी काम करता है। कम से कम 30-40 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें।

स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं

फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार बनाए रखें और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय और अतिरिक्त नमक का सेवन सीमित करें। धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये आदतें हृदय रोग के खतरे को और बढ़ा सकती हैं।

पर्याप्त नींद लें

प्रत्येक रात पर्याप्त नींद लेने को प्राथमिकता दें, क्योंकि लंबे समय तक नींद की कमी तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है और हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रति रात 7-9 घंटे की निर्बाध नींद का लक्ष्य रखें।

पेशेवर मदद लें

यदि आप पुराने तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेने में संकोच न करें।

गर्मियों में इन सुपरफूड्स का सेवन करने से हेल्दी रहेंगे आप, हीटवेव से बचने में मिलेगी मदद

हाई टेंपरेचर की वजह से कई बार लोगों को दस्त, कब्ज, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या होने लगती है। ऐसे में जरूर है कि सही और संतुलित खाने को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया जाए।

गर्मियों के मौसम में घर से बाहर निकलना आखिर किसे पसंद होता है। क्योंकि जरा सा बाहर निकलते ही थकान व कमजोरी महसूस होने लगती है। जिसकी सबसे बड़ी वजह चिलचिलाती धूप है। गर्मियों में हाई टेंपरेचर की वजह से पाचन तंत्र प्रभावित होता है। हाई टेंपरेचर की वजह से कई बार लोगों को दस्त, कब्ज, उल्टी और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या होने लगती है। ऐसे में जरूर है कि सही और संतुलित खाने को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया जाए। साथ ही इससे आप अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप खुद को गर्मियों में एनर्जेटिक कैसे रख सकते हैं।

बता दें कि गर्मियों में शरीर का पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। वहीं गर्मियों में फास्ट फूड या जंक फूड को पचाने के लिए पाचन तंत्र को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण से गर्मी के मौसम में हैवी खाना खाने के बाद सुस्ती और थकान लगने लगती है।

सत्तू का सेवन

झुलसती और चिलचिलाती गर्मी में थकान को दूर करने के लिए सत्तू एक बेहद शानदार सुपरफूड है। रोस्टेड या भुने चने को पीसकर सत्तू बनाया जाता है। इसके अलावा जौ को पीसकर सत्तू बनाया जाता है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है। इसके सेवन से शरीर हाइड्रेट रखने के साथ तापमान को कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह पेट को ठंडक पहुंचाता है और अपच से बचाता है। पानी, जीरा और सौंफ जैसे पाचक मसालों के लिए मिलाकर आप सत्तू का खाली पेट सेवन कर सकते हैं।

झुलसती गर्मी में थकान को दूर करने के लिए सत्तू एक बेहद शानदार सुपरफूड है। सत्तू रोस्टेड चने यानी भुने हुए चने को पीस कर बनाया जाता है। जौ को पीस कर भी सत्तू बनाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है जिससे शरीर को हाइड्रेट करने और तापमान को कम करने में मदद करता है। यह पेट को ठंडक भी देता है और अपच से भी बचाता है। आप इसे पानी और जीरा और सौंफ जैसे पाचक मसालों के साथ मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं।

गर्मियों में घी का सेवन

गर्मियों में घी को सबसे अच्छा सुपरफूड्स माना जाता है। घी में विटामिन A, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो शरीर को एनर्जी देने में सहायक होता है। वहीं घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को ठंडा रखने में सहायक होता है। गर्मियों में रोजाना खाली पेट आधा चम्मच घी का खाना चाहिए। यह गैस्ट्रिक एसिड के सोर्स को उत्तेजित कर पाचन कार्य में सुधार करता है।

रोजाना खाएं दही

गर्मी के मौसम में रोजाना दही का सेवन फायदेमंद होता है। दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और यह पेट व आंतों की गर्मी को दूर करने में कारगर होता है। दही के रोजाना सेवन से गर्मी में लू, कब्ज, अपच जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसमें मौजूद विटामिन B, फास्फोरस और जिंक त्वचा को हेल्दी रखता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है।

पुदीना और तुलसी की पत्तियां एलर्जी से बचाए

पुदीना और तुलसी की पत्तियों को गर्मियों में खाना लाभकारी होता है। क्योंकि पुदीना की पत्तियों में पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने, सिरदर्द में राहत देने और सांसों की दुर्गंध को दूर करने में मदद करती है। पुदीना की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो मुंहासों और एलर्जी से बचाते हैं। वहीं तुलसी की पत्तियों में विटामिन A, K और C के साथ मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। जो तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। आप इन दोनों को लिक्विड या खाने के फॉम में ले सकते हैं।

लौकी

लौकी में भी विटामिन सी के साथ मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। जो इम्यून सिस्टम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ सूजन को भी कम करने में सहायक होता है।

भिंडी

भिंडी में फोलेट, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है। भिंडी में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या से बचाता है। भिंडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।

प्याज

गर्मियों में रोजाना प्याज का सेवन करने से हीट-स्ट्रोक जैसी समस्या नहीं होती है। क्योंकि प्याज में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो धूप से होने वाले सेलुलर डेमेज के दुष्प्रभावों को बेअसर करने में सहायता करती है। प्याज को खाने के अलावा सलाद में भी शामिल कर सकते हैं।

तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार चलाने का अरविंद केजरीवाल का दावा हुआ फुस्स!

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अहम फैसला न होने के कारण मेयर चुनाव पड़ गया टालना। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज नहीं होगा। इसकी वजह सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल में होना है। **मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने में सीएम की राय का होना जरूरी है।** संबंधित फाइल को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर भेजा था, लेकिन वहां से लिखकर बताया गया कि फाइल पर सीएम केजरीवाल की संस्तुति लेना संभव नहीं है। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने चुनाव टालने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौजूदा मेयर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर को फिलहाल काम करने के लिए कहा है। **दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल की संस्तुति न मिलने पर मेयर चुनाव टालने का फैसला किया।** लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बताया गया है कि वो बतौर प्रशासक इस मामले में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर सीएम केजरीवाल के अलावा किसी और मंत्री को संस्तुति करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टालने के अलावा फिलहाल और कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम का पद किसी और को नहीं दिया है। **केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा था कि वे तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन इसमें पहला पेच मेयर चुनाव को लेकर ही फंस गया और केजरीवाल का दावा फुस्स हो गया है।** दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट ने 2 बार अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर दिया। रिमांड खत्म होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। वहीं, जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शराब घोटाला में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया है। शराब घोटाला मामले में तमाम आरोपी जेल में हैं। इनमें केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी हैं। जबकि, सांसद संजय सिंह को बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय को आखिर जनहित में करनी पड़ी टिप्पणी, आखिर क्यों, जाने

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दल्लि नगर नगिम (एमसीडी) को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है. दल्लि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार और एलजी की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैरमौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में हैं। इस दलील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आपकी पसंद है और कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार यह कहा है लेकिन यह आपके प्रशासन का फैसला है. अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम इस पर जनहित के लिए विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वह सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे. वकील फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने का कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है. फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है।

द्वारका से ड्रेस खरीदकर बना सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट, ID कार्ड लटका कर घूम रहा, जब खुली पोल तो...

आईजीआई थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो पायलट की वेशभूषा में घूम रहा था। उसने बकायदा आईडी कार्ड भी गले में लटका रखा था और जब कोई उससे पूछता था तो वह बताता था कि वह सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines) में पायलट है। पुलिस ने जब उसकी जांच की पता चला कि वह पायलट नहीं है। उसने नकली आईडी कार्ड बना रखा है।

नई दिल्ली। आईजीआई थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो पायलट की वेशभूषा में घूम रहा था। उसने बकायदा आईडी कार्ड भी गले में लटका रखा था और जब कोई उससे पूछता था तो वह बताता था कि वह सिंगापुर एयरलाइंस में पायलट है। पुलिस ने जब उसकी जांच की पता चला कि वह पायलट नहीं है। उसने नकली आईडी कार्ड बना रखा है और ड्रेस भी उसने द्वारका से खरीदी थी। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के संगीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा क्यों किया था।

CISF कर्मियों को बताया पायलट

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट की वर्दी पहने युवक को मेट्रो स्काईवॉक इलाके में घूमते देखा गया था। सीआईएसएफ कर्मियों के सामने उसने खुद को सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट बताते हुए अपने गले में लटका हुआ एक आईडी कार्ड दिखाया।

आईडी कार्ड की जांच की गई

जब उसका सत्यापन किया गया तो वह नकली मिला। जांच के दौरान पता लगा कि उसने बिजनेस कार्ड मेकर नामक ऐप का प्रयोग करके जाली आईडी कार्ड बनाया था। उसने द्वारका सेक्टर से पायलट की ड्रेस खरीदी थी।

घरवालों को किया गुमराह

पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि उसने वर्ष 2020 में मुंबई से एक साल का एविएशन हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया था। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस का पायलट होने का दावा करके स्वजन को गुमराह किया था। आईजीआई थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बृजभूषण सिंह को दिल्ली कोर्ट से लगा झटका, मामले में आगे की जांच कराने की याचिका खारिज

परिवहन विशेष न्यूज

महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी। सिंह ने याचिका दायर कर मामले की आगे की जांच कराने की मांग की है। बृजभूषण ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि सात सितंबर 2022 को जब यौन उत्पीड़न की बात हो रही है तब वह विदेश में थे।

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज कर दी। सिंह ने याचिका दायर कर मामले की आगे की जांच कराने की मांग की है।

बृजभूषण ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि सात सितंबर 2022 को जब यौन उत्पीड़न की बात हो रही है तब वह विदेश में थे। उन्होंने मांग करी थी कि इसकी सीडीआर रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस कोर्ट में जमा करे। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत अब सात मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश सुनाएंगी।

दिल्ली का यह हॉट सीट बना केजरीवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, 10 विधानसभा सीटों में से सात में हैं आप के विधायक

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर अब तक सजे चुनावी मैदान में भाजपा और I.N.D.I.A. गठबंधन समर्थित आप के प्रत्याशी उतरे हैं। मौजूदा वक्त में इस सीट के हिस्से में शामिल गांधी नगर लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं। वहीं शाहदरा कृष्णा नगर त्रिलोकपुरी पटपड़गंज कोंडली ओखला और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आप के विधायक हैं।

लोकसभा चुनाव-2019

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा	आप	कांग्रेस
जंगपुरा	41552	16894	24237
ओखला	55170	43921	60858
त्रिलोकपुरी	73885	25113	22712
कोंडली	66587	26095	18886
पटपड़गंज	86150	24997	20434
लक्ष्मी नगर	82650	21200	25666
विश्वास नगर	79721	15537	25399
कृष्णा नगर	82689	18695	36541

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट आप विधायकों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि इस सीट के अंतर्गत आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में से सात पर आप के विधायक हैं। ऐसे में आप प्रत्याशी को जीत दिलाने का दारोमदार इनके कंधों पर आ गया है। भाजपा के तीन ही विधायक यहां पर हैं, लेकिन ये पिछले दो लोकसभा चुनावों के आंकड़े देख कर खुश हैं। उन पर गौर करने से पता चलता है कि इस सीट की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है।

भाजपा और आप के प्रत्याशी उतरे

इस सीट पर अब तक सजे चुनावी मैदान में भाजपा और I.N.D.I.A. गठबंधन समर्थित आप के प्रत्याशी उतरे हैं। मौजूदा वक्त में इस सीट के हिस्से में शामिल गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं।

वहीं शाहदरा, कृष्णा नगर, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, कोंडली, ओखला और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आप के विधायक हैं। इस तस्वीर को देखने पर आप के लिए राह आसान लगती है। लेकिन, आंकड़े अलग कहानी बयान करते है। कांग्रेस गठबंधन में इनके साथ है, अगर उसके हिस्से का वोट मिल जाए तो राह आसान हो सकती है।

2019 में भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान बढ़ा

वर्ष 2014 में इस सीट पर भाजपा के पक्ष में 571567, आप के पक्ष में 381642 और कांग्रेस के लिए 203099 वोट पड़े थे। वहीं वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान बढ़ा था, लेकिन आप के पक्ष में ओखला को छोड़कर बाकी विधानसभा क्षेत्रों में वोट कम हो गए थे। इस चुनाव में भाजपा के खाते में 695109, आप को 219156 और कांग्रेस को 304718 वोट मिले थे।

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का कारण न बन जाए ये चुनाव, एलजी का रूख दे रहा स्पष्ट संकेत

परिवहन विशेष न्यूज

एमसीडी के पूर्व मुख्य विधि अधिकारी अनिल गुप्ता ने बताया कि एमसीडी एक्ट का उल्लंघन रोकने के लिए जरूरी है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो। यह तब ही होगी जब सीएम जेल से बाहर आकर फाइल साइन करें। या फिर कोर्ट इसमें कुछ दिशा-निर्देश जारी करें। अगर कोर्ट से इसका रास्ता नहीं निकलता है तो एलजी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ठोस वजह मिल जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली में महापौर चुनाव क्या राष्ट्रपति शासन की वजह बन सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उपराज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो सीएम सलाह देकर फाइल महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी फाइल भेजें।

अब ऐसे में जेल से सरकार चलाने पर अड़ी आम आदमी पार्टी के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए या तो कोर्ट से कोई निर्णय हो या फिर सीएम जेल से बाहर आने के बाद इस पर निर्णय ले, तब ही दिल्ली को नया महापौर मिल सकता है।

राष्ट्रपति शासन के बाद ही एलजी ले सकते हैं फैसला

अगर, सीएम जेल से बाहर नहीं आते हैं और कोर्ट से भी इस मुद्दे का समाधान नहीं निकलता है तो संभवतः यह प्रक्रिया तब ही एलजी स्वयं पूरी कर सकते हैं जब दिल्ली में चुनी हुई सरकार न हो। ऐसा तब ही हो सकता है, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हो।

विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली में महापौर चुनने का यह तीसरा वर्ष है और महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में इस पद पर सामान्य श्रेणी के महापौर के कार्यकाल को ज्यादा दिनों तक विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

एलजी के रुख से हो रहा स्पष्ट: अनिल गुप्ता

दिल्ली नगर निगम के पूर्व मुख्य विधि अधिकारी अनिल गुप्ता बताते हैं कि एलजी के रुख से स्पष्ट है कि वह जब तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक की सीएम इसमें सलाह न दे दें। लेकिन, यह रुख सही है या गलत है, इसका निर्णय कोर्ट कर सकता है। क्योंकि मनोनीत सदस्यों के चयन में उपराज्यपाल ने सीएम की सलाह की जरूरत से इनकार किया था। अब एलजी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए सीएम की सलाह को जरुरी बता रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि एमसीडी में महापौर पद में तीसरे वर्ष के लिए चुनाव होना है। ऐसे में यह पद इस वर्ष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है इसलिए अनुसूचित जाति के पार्षद को इस वर्ष ही महापौर बनाना होगा नहीं तो यह एमसीडी एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा।

राष्ट्रपति शासन को मिलेगी ठोस वजह: अनिल गुप्ता

उन्होंने कहा कि एमसीडी एक्ट का उल्लंघन रोकने के लिए जरुरी है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो। यह तब ही होगी जब सीएम जेल से बाहर आकर फाइल साइन करें। या फिर कोर्ट इसमें कुछ दिशा-निर्देश जारी करें।

अगर, कोर्ट से इसका रास्ता नहीं निकलता है तो एलजी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की ठोस वजह मिल जाएगी। पहले से ही तीन हजार फाइलें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लंबित है। इससे लग रहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट बढ़ रहा है। इस संकट को टालने के लिए एलजी ठोस निर्णय ले सकते हैं।

सही निकली आशंका

एक समाचार पत्र ने सीएम के जे ल जाने के बाद दो अप्रैल को प्रकाशित समाचार में इस आशंका को जाहिर किया था। क्योंकि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में सीएम की भूमिका काफी अहम होती है। अब तक सीएम ही एलजी को इससे संबंधित फाइलें भेजते रहे हैं। उनके जेल में जाने से यह समस्या आनी स्वभाविक भी थी।

अब सवाल यह है कि अगर, सीएम जल्द ही जेल से बाहर नहीं आए या फिर इससे संबंधित फाइल उनकी सलाह के साथ नहीं गई तो दिल्ली में संवैधानिक संकट गहरा सकता है। नौबत निगम को भंग करने तक की आ सकती है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक्ट हर वर्ष अप्रैल में होने वाली बैठक में महापौर व उप महापौर का चुनाव कराया जाता है।

कैसे जाती है फाइल उपराज्यपाल के पास

निगम सचिव - कमीश्नर को यह फाइल भेजते हैं।

निगम कमीश्नर- शहरी विभाग के सचिव को फाइल भेजते हैं

शहरी विकास विभाग के सचिव- मुख्य सचिव को फाइल भेजते हैं

मुख्य सचिव - शहरी विकास विभाग के मंत्री को फाइल भेजते हैं

शहरी विकास विभाग के मंत्री- मुख्यमंत्री को यह फाइल भेजते हैं

मुख्यमंत्री - उपराज्यपाल को यह फाइल भेजते हैं।

एलजी के फैसले की कांग्रेस ने भी की निंदा

प्रदेश कांग्रेस एमसीडी प्रभारी जितेंद्र कुमार कोचर ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महापौर और उप महापौर चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी के बावजूद वोटिंग पर एलजी द्वारा रोक लगाने को संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के अनुसूचित जाति समाज का अपमान है।

कोचर ने कहा कि दिसंबर 2022, जब से नगर निगम में भाजपा का शासन खत्म हुआ है, हर बार महापौर चुनाव में भाजपा की औछी राजनीति और स्वयंभू बने रहने की सोच के कारण अड़चनें आ रही हैं। पिछले दो वर्षों से निगम में स्थायी समिति, जोन व वार्ड कमेटियों का गठन तक नही हो पाया है।

आप ने बताया बीजेपी को एससी विरोधी मानसिकता

वरिष्ठ पार्टी नेता और आप सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि एमसीडी एक्ट के अनुसार, एमसीडी के तीसरे साल में महापौर का पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है। इस बार महापौर का चुनाव रद कर भाजपा ने अपनी अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता दिखा दी है।

आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि एलजी साहब चुनाव रद करने का कारण बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। इसमें सीएम की इजाजत नहीं मिली है। इससे पहले सीएम ने दिल्ली के हक में हजारों सलाह दी हैं, पर एलजी साहब ने आज तक उस पर काम नहीं किया।

एमसीडी सदन की बैठक में आमने-सामने हुए बीजेपर-आप, जमकर हुई नारेबाजी; कार्यवाही स्थगित

दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में शुक्रवार को भाजपा और आप के पार्षद आमने-सामने आ गए। आप के पार्षदों ने निगम मुख्यालय में डॉ. अंबेडकर की मूर्ति के पास भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। फिर सदन में पहुंच भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक चली नारेबाजी के बाद मेयर ने सदन की कार्यवाही स्थगित की।

नई दिल्ली। महापौर चुनाव टलने के बाद दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक की शुरूआत हंगामे से हुई। पहले भाजपा पार्षदों ने महापौर के आसन के पास घेरा बना लिया। फिर थोड़ देर महापौर को सदन में बुलाने की मांग को लेकर भाजपा नारेबाजी की। वहीं, आप के पार्षदों ने निगम मुख्यालय में डॉ. अंबेडकर की मूर्ति के पास भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। फिर सदन में पहुंच भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा और आप पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक चली नारेबाजी के बाद महापौर डॉ. शैली ओबेराय निगम सदन में पहुंची।

अगली बैठक तक सदन की कार्यवाही स्थगित

इसके बाद महापौर ने कहा कि सीएम का बहाना लगाकर एलजी साहब ने संविधान की हत्या की। इससे पहले भी महापौर और उप महापौर के चुनाव होते रहे हैं। महापौर ने अगली बैठक तक के लिए निगम सदन की बैठक को स्थगित कर दिया।

बीजेपी पार्षद झूमते नजर आए

वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के पार्षदों को नाचते-झूमते नजर आए। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद आप ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सका मतदान प्रतिशत, 6 फीसदी की आई गिरावट

पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो गाजियाबाद में करीब 55.78 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान में करीब छह प्रतिशत की गिरावट आई है। मतदान का प्रतिशत गिरने से सभी सियासी दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि जिन मतदाताओं ने वोट न करके किस सियासी दल को चोट पहुंचाई है।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। लोकतंत्र के महापर्व में इस बार गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में 49.80 प्रतिशत ही मतदान हुआ। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव सा उत्साह लोगों में नहीं दिखाई दिया। सुबह मतदान की रफ्तार धीमी रही। धीरे-धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन शाम छह बजे तक भी इसकी रफ्तार 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी।

पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 55.78 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान में करीब छह प्रतिशत की गिरावट आई है। मतदान का प्रतिशत गिरने से सभी सियासी दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि जिन मतदाताओं ने वोट न करके किस सियासी दल को चोट पहुंचाई है।

मतदान गिरने की वजह एक तरफ प्रशासन की लापरवाही रही तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों की ओर से उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर मतदाताओं में असंतोष भी है। इसके साथ ही बढ़ी संख्या में ऐसे मतदाता है जिनकों प्रत्याशी यह विश्वास नहीं दिला पाए कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

अपने घरों से बाहर हीं नहीं निकले लोग

नतीजा यह रहा कि प्रत्याशियों से नाराज मतदाता मतदान के लिए अपने घरों से बाहर हीं नहीं निकले। यही वजह रही कि जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया पोलिंग सेंटर पर कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जिन पर सन्नाटा दिखाई दिया।

यहां पर मतदान कराने के लिए तैनात किए अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं सियासी दलों की ओर से बनाए गए पोलिंग एजेंट मतदाताओं की राह तकते नजर आए। जब मतदाता दोपहर बाद तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे तो सियासी दल के नेताओं ने फोन मिलाना शुरू किया। फोन के माध्यम से मतदाताओं मान-मनौव्वल तक की गई। लेकिन अंत तक भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से अधिक नहीं पहुंचा पाए। बमुश्किल 50 प्रतिशत पहुंच सका।

वर्ष 2014 से गिरता चला आ रहा है मतदान प्रतिशत

बीते लोकसभा चुनावों की बात करें तो वर्ष 2009 में करीब 45.30 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके बाद वर्ष 2014 में गाजियाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उत्साह दिखाया और मतदान का प्रतिशत बढ़कर 56.05 तक पहुंच गया। लेकिन लोगों का यह उत्साह बरकरार नहीं रह सका।

वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वोट करने के प्रति उतने जागरूक नहीं दिखाई दिए और यह मतदान प्रतिशत घटकर 55.78 प्रतिशत पर पहुंच गया। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत से एक बात साफ होती नजर आ रही है कि लोग अपने मताधिकार के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।

नाकाफी साबित हुई आयोग की तैयारी

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने तमाम जतन किए, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। प्रशासन की ओर से कभी लोगों को जागरूक करने के लिए वाकथान का आयोजन किया गया तो कभी उन्हें शपथ दिलाई गई। स्कूल-कॉलेजों में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया पर सारे प्रयास विफल हो गए। प्रशासन के कोई भी कार्यक्रम मतदाताओं को मतदान केंद्र लाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके और मतदान प्रतिशत पिछली बार से घटकर 49.80 प्रतशित पर पहुंच गया।

गाजियाबाद में प्रत्याशियों की बढ़ी धड़कनें, कम मतदान प्रतिशत क्यों बनी वजह?

लोकतंत्र के महापर्व में इस बार गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में 49 .80 प्रतिशत ही मतदान हुआ। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव सा उत्साह लोगों में नहीं दिखाई दिया। सुबह मतदान की रफ्तार धीमी रही। धीरे-धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन शाम छह बजे तक भी इसकी रफ्तार 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी।

गाजियाबाद। लोकतंत्र के महापर्व में इस बार गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में 49.80 प्रतिशत ही मतदान हुआ। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव सा उत्साह लोगों में नहीं दिखाई दिया। सुबह मतदान की रफ्तार धीमी रही। धीरे-धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन शाम छह बजे तक भी इसकी रफ्तार 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी।

पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 55.78 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान में करीब छह प्रतिशत की गिरावट आई है। मतदान का प्रतिशत गिरने से सभी सियासी दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि जिन मतदाताओं ने वोट न करके किस सियासी दल को चोट पहुंचाई है।

मतदान गिरने की वजह एक तरफ प्रशासन की लापरवाही रही तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों की ओर से उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर मतदाताओं में असंतोष भी है। इसके साथ ही बढ़ी संख्या में ऐसे मतदाता है जिनकों प्रत्याशी यह विश्वास नहीं दिला पाए कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

नतीजा यह रहा कि प्रत्याशियों से नाराज मतदाता मतदान के लिए अपने घरों से बाहर हीं नहीं निकले। यही वजह रही कि जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया पोलिंग सेंटर पर कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जिन पर सन्नाटा दिखाई दिया। यहां पर मतदान कराने के लिए तैनात किए अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं सियासी दलों की ओर से बनाए गए पोलिंग एजेंट मतदाताओं की राह तकते नजर आए।

जब मतदाता दोपहर बाद तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे तो सियासी दल के नेताओं ने फोन मिलाना शुरू किया। फोन के माध्यम से मतदाताओं मान-मनौव्वल तक की गई। लेकिन अंत तक भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से अधिक नहीं पहुंचा पाए। बमुश्किल 50 प्रतिशत पहुंच सका।

वर्ष 2014 से गिरता चला आ रहा है मतदान प्रतिशत

बीते लोकसभा चुनावों की बात करें तो वर्ष 2009 में करीब 45.30 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके बाद वर्ष 2014 में गाजियाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उत्साह दिखाया और मतदान का प्रतिशत बढ़कर 56.05 तक पहुंच गया। लेकिन लोगों का यह उत्साह बरकरार नहीं रह सका। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वोट करने के प्रति उतने जागरूक नहीं दिखाई दिए और यह मतदान प्रतिशत घटकर 55.78 प्रतिशत पर पहुंच गया। लेकिन इस बार के मतदान प्रतिशत से एक बात साफ होती नजर आ रही है कि लोग अपने मताधिकार के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।

नाकाफी साबित हुई आयोग की तैयारी

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने तमाम जतन किए, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। प्रशासन की ओर से कभी लोगों को जागरूक करने के लिए वाकथान का आयोजन किया गया तो कभी उन्हें शपथ दिलाई गई। स्कूल-कालेजों में कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया पर सारे प्रयास विफल हो गए। प्रशासन के कोई भी कार्यक्रम मतदाताओं को मतदान केंद्र लाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके और मतदान प्रतिशत पिछली बार से घटकर 49.80 प्रतशित पर पहुंच गया।

विषम परिस्थितियों को पीछे छोड़ दिव्यांगों ने आगे बढ़कर किया मतदान

गाजियाबाद के मकनपुर के नगर निगम कन्या विद्यालय में दोपहर सुबह करीब 753 बजे दिव्यांग सुरेश त्यागी अपने बेटे व पुत्रवधू के साथ मतदान करने पहुंचे। व्हीलचेयर पर बैठे सुरेश त्यागी के चेहरे पर मतदान के लिए अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना हमारा अधिकार है। लोगों को देश के लिए आगे आकर मतदान करना चाहिए।

परिवहन विशेष न्यूज

दिव्यांगता व अन्य कोई भी परेशानी आपको मतदान करने से नहीं रोक सकती। अर्थला के दिव्यांग विजय वसुंधरा सेक्टर-एक स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। ई-रिक्शा में बैठे विजय ने मतदान के बाद अंगुली दिखाकर दूसरों को भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी वोट करने नहीं जाते।

गाजियाबाद। पांच साल बाद देश की सरकार बनाने में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है। ऐसे में मतदान के संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छे सांसद व सरकार के लिए विषम परिस्थितियों को पीछे छोड़ आगे आकर मतदान करना बहुत जरूरी है। यह कहना है वसुंधरा सेक्टर-15 में मतदान करने पहुंचे दिव्यांग भूपेंद्र का।

मकनपुर के नगर निगम कन्या विद्यालय में दोपहर सुबह करीब 7:53 बजे दिव्यांग सुरेश त्यागी अपने बेटे व पुत्रवधू के साथ मतदान करने पहुंचे। व्हीलचेयर पर बैठे सुरेश त्यागी के चेहरे पर मतदान के लिए अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना हमारा अधिकार है। लोगों को देश के लिए आगे आकर मतदान करना चाहिए।

दिव्यांगता आपको मतदान से नहीं रोक सकती

दिव्यांगता व अन्य कोई भी परेशानी आपको मतदान करने से नहीं रोक सकती। अर्थला के दिव्यांग विजय वसुंधरा सेक्टर-एक स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। ई-रिक्शा में बैठे विजय ने मतदान के बाद अंगुली दिखाकर दूसरों को भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी वोट करने नहीं जाते।

कुष्ठ आश्रम से मतदान करने पहुंचे

कुष्ठ आश्रम में रहने वाले दिव्यांग राजकुमार भी केला भट्टा स्थित मतदान केंद्र पर वोट करने पहुंचे। करीब दो किलोमीटर की दूरी ई-रिक्शा से तय कर उन्होंने मतदान किया। उनका कहना है कि वोट करना हमारा अधिकार है। लोगों को बढ़चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। दूसरे कामों को छोड़कर मतदान करना बहुत जरूरी है। एक-एक वोट से हम सांसद चुनते हैं। इसके बाद चुने गए सांसद सरकार बनाते हैं। अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट बहुत जरूरी है।

गाजियाबाद में कुल 13719 दिव्यांग मतदाता

गाजियाबाद लोकसभा सीट में कुल 13719 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान के लिए सुबह से ही दिव्यांग मतदाता पहुंचने शुरू हो गए। देर शाम तक दिव्यांग केंद्रों पर पहुंचे। द्वियांगों के लिए बूथों पर व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया था। हालांकि केवल एक व्हीलचेयर होने से दिव्यांगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी।

नोएडा की सोसायटियों में डब्ल्यूएफएच करने वालों को राहत, ईसी के इस कदम से 40 हजार मतदाता डाल पा रहे वोट

निर्वाचन आयोग की तरफ से नोएडा की बहुमंजिला सोसायटियों में पहली बार बनाए गए 100 मतदान केंद्रों से वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। वह ब्रेक लेकर मतदान के लिए निकल रहे हैं। मतदान केंद्र दूर होने से इनमें से बड़ी संख्या में लोग मतदान करने से रह जाते थे।

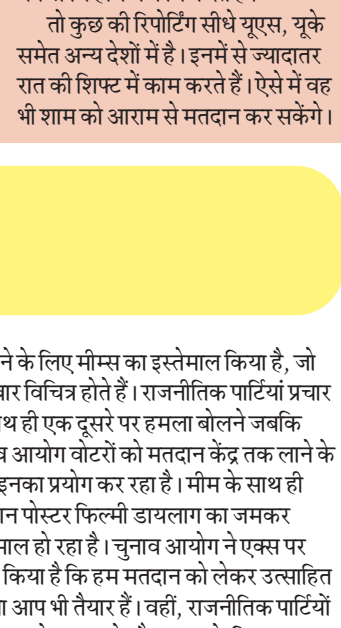

नोएडा। निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुमंजिला सोसायटियों में पहली बार बनाए गए 100 मतदान केंद्रों से वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। वह ब्रेक लेकर मतदान के लिए निकल रहे हैं। मतदान केंद्र दूर होने से इनमें से बड़ी संख्या में लोग मतदान करने से रह जाते थे।

गुरुग्राम बेस्ड कान्टिनम कंपनी में काम करने वाले गौरव उपाध्याय ने बताया कि वर्क फ्राम होम में काम कर रहे हैं। मतदान के लिए दो घंटे का ब्रेक मिला है।

उनका कहना है कि बाहर होने पर वह तो चले जाते लेकिन उनकी तरह सोसायटी में चार-पांच सौ लोग हैं। हर कोई जा पाता ये कहना मुश्किल है। अब ज्यादातर ने ग्रुप पर वोट के लिए सहमति दी है।

'यह एक सराहनीय कदम'

मुंबई बेस्ड कंपनी स्विटजर में काम करने वाले मेहुल प्रतीक लॉरेल सोसायटी एओए के पदाधिकारी है और नोएडा में रहकर वर्क फ्राम होम ही काम करते हैं।

उन्होंने बताया कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। नोएडा में लगभग 40 हजार ऐसे मतदाता हैं। सोसायटी परिसर में मतदान होने से एओए का भी आग्रह है। ऐसे में ज्यादातर मतदान कर रहे हैं।

बहुमंजिला सोसायटियों में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादतर के आफिस बेंगलुरु, पुणे, मुंबई व गुरुग्राम है और वह वर्क फ्राम होम में काम करते हैं।

तो कुछ की रिपोर्टिंग सीधे यूएस, यूके समेत अन्य देशों में है। इनमें से ज्यादातर रात की शिफ्ट में काम करते हैं। ऐसे में वह भी शाम को आराम से मतदान कर सकेंगे।

सियासत के संग्राम में नारों का जोर-शोर

1977 में जननायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया था। उस साल जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की और इसमें इस नारे का बहुत बड़ा हाथ था।

अजय कुमार

चुनाव के बनते-बिगड़ते समीकरणों के बीच चुनावी नारे खूब रंग जमाते रहे हैं। शुरुआती चुनाव से मौजूदा दौर तक चुनावी नारे सियासी दलों की विचारधारा की तस्वीर को जनता के बीच साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इन्हीं नारों की पतवार के सहारे कई पार्टियों की नैया भी पार लगी है तो कई बार कुछ नारे जमीदोज भी हो गये। अब तो चुनावी नारों के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने तक, लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के कई हास्य तत्वों सहित रंगीन मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ भी देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावों से पहले राजनीतिक बढ़त के लिए कड़वे पोस्टर युद्ध और यहां तक कि कड़वे मीम की लड़ाई भी देखी जा सकती है। मतदाताओं, विशेषकर युवा और पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया है, जो कई बार विचित्र होते हैं।

लोकसभा चुनाव में सबसे पहला लोकप्रिय नारा सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ रहा। इस नारे की गूंज गली-गली तक रही और इंदिरा गांधी को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। असल में 1967 में जब इंदिरा गांधी चुनाव मैदान में उतरीं तो उस दौरान कांग्रेस का नारा सरकार बनाना खेल नहीं, इस दीपक में तेल नहीं सियासी फिजाओं में खूब गूंजा था, लेकिन 1971 में गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी ने लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम करने में सफलता हासिल की। आम लोगों के दिल को छूने वाला यही नारा एक बड़ा मुद्दा बन गया। चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी लोगों से कहती थीं कि वह कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इसी पर इंदिरा के समर्थन में एक और नारा लोकप्रिय हुआ...जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर।

1977 में जननायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया था। उस साल जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की और इसमें इस नारे का बहुत बड़ा हाथ था। 1996 और 1998 के चुनावी मैदान में राजतिलक की करो तैयारी आ रहे अटल बिहारी को खूब लोकप्रियता मिली, लेकिन इसके बाद हुए आम चुनाव में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग नारा पूरी तरह से धाराशायी हो गया था। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुलायम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं भी खूब गूंजा था। 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव में हर-हर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी चुनावी रणक्षेत्र में खूब गूंजा। भाजपा की हर रैली में इस नारे का शोर रहा। इसका असर यह रहा कि 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा।

आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के लिए नारों का शोर गली-मोहल्लों में भले ही न सुनाई दे रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंच बना रहे हैं। इनका असर पहले से अधिक प्रभावी है। आजादी के बाद हुए आम चुनाव से अभी तक नारों के तेवर ने बनते बिगड़ते समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कब जनता के बीच कौन सा नारा सिर चढ़ कर बोला इसकी बात की जाये तो वर्ष 1952 में खरा रुपैया चांदी का, राज महात्मा गांधी का और देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है खूब हवा में उछला था। इसी तरह वर्ष 1957 में जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखा दीपक का खेल, जिस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। वर्ष 1962 में, जाटव-मुस्लिम भाई-भाई, बाकी कौम कहां से आई। सिंहासन खाली करो जनता आती है। वर्ष 1967 में जय जवान जय किसान। वर्ष 1977 में बेटा कार बनाएगा, मां सरकार बनाएगी। यह नारा संजय गांधी और इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हुए गढ़ा गया था। इसी के साथ जमीन गर्क चकबंदी में, मकान ढह गया हटबंदी में। दरवाजे पर खड़ी औरतें चिल्लाएं, मेरा मर्द गया नसबंदी में भी काफी प्रभावी रहा था।

वर्ष 1980 में इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, का नारा लगा। वर्ष 1984 में जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। उठे करोड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं। वर्ष 1996 में 'सबको देखा बारी-बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।' महंगाई जो रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वर्ष 2004 में शाइनिंग इंडिया, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ नारे की धूम रही थी। वर्ष 2014 में 'अबकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी। वर्ष 2019 में 'सबका साथ सबका विकास', 'मोदी है तो मुमकिन है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, अब होगा न्याय। इस बार वर्ष 2024 में मोदी की गांरटी, अबकी पार 400 पार। कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात सपा का 'घर घर बेरोजगार मांगे रोजगार" नारा चर्चा है।

अब तो चुनावी नारों के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने से लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने तक, लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के कई हास्य तत्वों सहित रंगीन मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ भी देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावों से पहले राजनीतिक बढ़त के लिए कड़वे पोस्टर युद्ध और यहां तक कि कड़वे मीम की लड़ाई भी देखी जा सकती है। मतदाताओं, विशेषकर युवा और पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया है, जो कई बार विचित्र होते हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर हमला बोलने जबकि चुनाव आयोग वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। मीम के साथ ही स्लोगन पोस्टर फिल्मी डायलाग का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम मतदान को लेकर उत्साहित हैं क्या आप भी तैयार हैं। वहीं, राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले और प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया है। भाजपा के सोशल मीडिया फीड पर मुख्य रूप से तस्वीरें और नारे हावी रहे हैं। जैसे मोदी की गारंटी और विकास भी, विरासत भी। वहीं, कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भाजपा पर व्यंग्यात्मक टैगलाइन, बेरोजगारी बहुत है, बाकी सब ठीक है, के साथ कटाक्ष किया गया।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के एक-दूसरे पर हमले जारी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें मीम मटीरियल ऑफ दि ईयर बताया। जिसके कैप्शन में लिखा, "ये अवॉर्ड तो बनता है।" दरअसल, बीते 09 मार्च को दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने क्रिएटर्स अवॉर्ड दिए। इसी दौरान की एक फोटो एडिट करके बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर की जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी को एक अवॉर्ड देते हुए दिख रहे हैं। इस अवॉर्ड पर 'जोकर' लिखा हुआ है। साथ ही अंग्रेजी में लाइन लिखी गई कि मीम मटीरियल ऑफ दि ईयर- राहुल गांधी। जिसका बीजेपी वालों ने कैप्शन लिखा, "ये अवॉर्ड तो बनता है।"

स्टैटिक का इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स को तोहफा! इन 4 राज्यों में फ्री चार्जिंग ऑफर कर रही कंपनी

Statiq ने कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में Electric Vehicle यूजर्स के लिए मुफ्त चार्जिंग की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि उसके नए अभियान का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना है। ईवी मालिकों को मुफ्त चार्जिंग सक्षम करने के लिए स्टेटिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। यह सर्विस प्लग-एंड-प्ले डिवाइस की तरह सरलता से काम करती है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। EV charging सॉल्यूशन प्रदाता कंपनी Statiq ने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में Electric Vehicle यूजर्स के लिए मुफ्त चार्जिंग की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि ये ऑफर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए उपलब्ध होगा।

Electric Mobility को बढ़ावा

कंपनी का कहना है कि उसके नए अभियान का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना है। स्टेटिक ने सबसे पहले कर्नाटक में अपना मुफ्त चार्जिंग अभियान शुरू किया और कंपनी का कहना है कि जबरदस्त प्रतिक्रिया ने उसे अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तार करने के लिए प्रेरित किया।

वर्तमान में कंपनी के पूरे कर्नाटक में 400 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट चालू हैं और कंपनी का कहना है कि इसका इंस्टॉलेशन Tata Nexon EV, MG ZS EV और Tata Tiago EV जैसे मॉडलों को सपोर्ट करता है। साथ ही ये Ather 450X, Ola S1 Pro और TVS iQube जैसे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को भी सपोर्ट करेगा।

ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ

ईवी मालिकों को मुफ्त चार्जिंग सक्षम करने के लिए स्टेटिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। यह सर्विस प्लग-एंड-प्ले डिवाइस की तरह सरलता से काम करती है और कंपनी का कहना है कि इसमें कोई हिडेन चार्ज शामिल नहीं है। इसके अलावा, उपभोक्ता अपने वाहनों को कई बार चार्ज कर सकते हैं और चार्जिंग पॉइंट पर वाहन को प्लग इन करने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

स्टेटिक के चार्जिंग प्वाइंट

स्टेटिक के चार्जिंग प्वाइंट 30 किलोवाट, 60 किलोवाट और 120 किलोवाट के बीच हैं। ऐप पर लिस्टेड सभी चार्जिंग प्वाइंट फास्ट चार्जर से लैस हैं। स्टेटिक के पास टियर I, II और III में सामूहिक रूप से 7,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, थार और XUV700 की डिलीवरी के लिए करना होगा इतना इंतजार

Mahindra Bolero एमयूवी का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है जबकि Thar के चुनिंदा वेरिएंट के लिए यह 43 सप्ताह तक है। स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट का वेटिंग पीरियड आठ सप्ताह तक है जबकि टॉप-स्पेक एस11 ट्रिम के लिए यह 20 सप्ताह तक है। स्कॉर्पियो एन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को बेस डीजल एमटी वेरिएंट के लिए 20 सप्ताह तक इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। Mahindra & Mahindra की ओर से अपने पॉपुलर मॉडलों पर वेटिंग पीरियड कम करने के लिए पर्दे के पीछे काम किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी कंपनी के पॉपुलर मॉडलों पर लंबा वेटिंग पीरियड है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Bolero, Scorpio और Scorpio N

कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली Mahindra Bolero एमयूवी का वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, जबकि Thar के चुनिंदा वेरिएंट के लिए यह 43 सप्ताह तक है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन को बाजार में पदार्पण के बाद से ही ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किया गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक मूल रूप से कॉस्मेटिक अपडेट के साथ पुरानी पीढ़ी की स्कॉर्पियो है, जबकि स्कॉर्पियो लैडर फ्रेम चेसिस पर आधारित एक ऑल न्यू पेशकश है।

स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट का वेटिंग पीरियड आठ सप्ताह तक है, जबकि टॉप-स्पेक एस11 ट्रिम के लिए यह 20 सप्ताह तक है। स्कॉर्पियो एन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को बेस डीजल एमटी वेरिएंट के लिए 20 सप्ताह तक इंतजार करना होगा।

Z8S, Z8 और Z8L AT ट्रिम्स की प्रतीक्षा अवधि 9 से 11 सप्ताह के बीच है। इसके अलावा Z4 पेट्रोल की नवीनतम प्रतीक्षा अवधि 12 से 18 सप्ताह के बीच है, जबकि Z6 की यह 14 से 16 सप्ताह के बीच है।

Mahindra Thar और XUV700

Mahindra Thar 4WD वर्जन में 6 से 8 सप्ताह के बीच वेटिंग पीरियड है। वहीं, 2WD हार्ड टॉप डीजल वेरिएंट के लिए 43 सप्ताह तक का लंबा वेटिंग पीरियड है। Thar 2WD हार्ड टॉप पेट्रोल 16 से 18 सप्ताह की प्रतीक्षा अवधि मांगता है।

हुंडई क्रेटा EV अगले साल होगी लॉन्च! कंपनी ने बताई फ्यूचर प्लानिंग, EV चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे

Kia India अगले साल यानी 2025 में अपनी पहली स्थानीय ईवी का उत्पादन भी शुरू करेगी और अधिक स्थानीय रूप से निर्मित ईवी के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। उम्मीद है कि भारत में हुंडई की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार Creta EV होगी जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Hyundai Motor India ने अपनी ईवी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और ऑटोमेकर के पास 2030 तक पाइपलाइन में 5 नई लोकली-बिल्ट पेशकश हैं। दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर ने अब पुष्टि की है कि उसकी पहली मेड-इन-इंडिया ऑल-इलेक्ट्रिक कार 2025 की शुरुआत तक आएगी और इसे चेन्नई के पास ब्रांड की तमिलनाडु सुविधा में बनाया जाएगा।

Hyundai Creta EV की तैयारी

उम्मीद है कि भारत में हुंडई की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार Creta EV होगी, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हुंडई मोटर ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष यूइसुन चुंग इस सप्ताह ग्रुप की मिड टू लॉन्ग टर्म भविष्य की रणनीति की समीक्षा करने के लिए भारत में थे और इसमें हुंडई और किआ दोनों ब्रांड शामिल हैं।

संभावित डिजाइन और स्पेसिफिकेशन

स्पॉट किए गए टेस्टिंग म्यूल से पता चलता है कि इसका डिजाइन स्टैंडर्ड क्रेटा और क्रेटा एन-लाइन से अलग होगा। उम्मीद है कि क्रेटा ईवी लगभग 400-500 किमी की रेंज पेश करेगी। Hyundai Creta EV और Kia Seltos EV की कीमतें भी 20-30 लाख रुपये के बीच होंगी। इन मॉडलों का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी400, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व, मारुति सुजुकी ईवीएक्स और बीवाईडी एट्टो 3 से होने वाला है।

कंपनी ने क्या कहा?

हुंडई इंडिया के लिए रणनीति को रेखांकित करते हुए, वाहन निर्माता ने कहा कि वह चालू वर्ष के अंत में आगामी हुंडई ईवी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। बिक्री अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है।

EV Charging Station भी बढ़ेंगे

किआ इंडिया 2025 में अपनी पहली स्थानीय ईवी का उत्पादन भी शुरू करेगी और अधिक स्थानीय रूप से निर्मित ईवी के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। दोनों कंपनियां ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। हुंडई इंडिया अपने बिक्री नेटवर्क केंद्रों का उपयोग करेगी और 2030 तक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 485 तक बढ़ाएगी।

धड़ाधड़ बिक रही Kia की ये SUV, केवल इतने दिनों में पार किया 4 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा

Kia Sonet ने भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत के 44 महीने से भी कम समय में 4 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा पार कर लिया है। किआ सोनेट के 63 प्रतिशत खरीदारों ने ऐसे मॉडल चुने हैं जो सनरूफ के साथ आते हैं। जहां तक इंजन प्राथमिकताओं की बात है 37 प्रतिशत ग्राहकों ने 1.5 लीटर डीजल इंजन का चयन किया है जबकि 63 प्रतिशत ने पेट्रोल इंजन विकल्प चुना।

नई दिल्ली। Kia Sonet ने भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत के 44 महीने से भी कम समय में 4 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने दक्षिण कोरियाई ऑटो प्रमुख की इंडियन मार्केट में बेहतरीन सेल कराई है। स्थानीय बाजार में किआ ने सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवी की 3,17,754 यूनिट सेल की हैं, जबकि 85,814 यूनिट आंध्र प्रदेश फैसिलिटी से एक्सपोर्ट की गईं।

इन वेरिएंट की सबसे ज्यादा मांग

किआ सोनेट के 63 प्रतिशत खरीदारों ने ऐसे मॉडल चुने हैं, जो सनरूफ के साथ आते हैं। जहां तक इंजन प्राथमिकताओं की बात है, 37 प्रतिशत ग्राहकों ने 1.5 लीटर डीजल इंजन का चयन किया है, जबकि 63 प्रतिशत ने पेट्रोल इंजन विकल्प चुना है। किआ ने सोनेट के ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए भी ग्राहकों के बीच बढ़ती प्राथमिकता देखी है।

2020 के बाद से 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन की लोकप्रियता में 37.50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। कंपनी इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट को डीसीटी और 6-स्पीड ऑटो के साथ बेचती है, जिसने कुल बिक्री में 28 प्रतिशत का योगदान दिया है। वहीं, इंटेलिजेंट मैनुअल ब्रांड के अनुसार ट्रांसमिशन (iMT) की कुल बिक्री में लगातार 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

हाल ही में हुई है अपडेट

हाल ही में किआ ने अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए डीजल और पेट्रोल इंजन विकल्पों में सोनेट के चार नए एचटीई (ओ) और एचटीके (ओ) वेरिएंट पेश किए हैं। जहां HTE (O) में सनरूफ मिलता है, वहीं HTK (O) में एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप, ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल और रियर डिफॉगर के साथ सनरूफ मिलता है।

कब हुई थी शुरुआत?

सेल्टोस मिडसाइज एसयूवी और ग्रैंड कार्निवल प्रीमियम एमपीवी के बाद, सब-फोर-मीटर एसयूवी को सितंबर 2020 में भारतीय बाजार के अंदर पेश किया गया था और ये कंपनी का तीसरा मॉडल था। CY 2024 की पहली तिमाही में प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसकी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950 RVE नए अवतार में हुई लॉन्च, जानिए पहले से कितनी बदली

Ducati India ने Hypermotard 950 RVE को नई कलर स्की के साथ पेश किया है। नई कलर स्कीम की बात करें तो ये कई स्पलैश-जैसे ग्राफिक्स के साथ आती है जो मोटरसाइकिल के बॉडी पैनल पर मौजूद हैं। डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950 आरवीई में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्रभावशाली सीरीज है। इसमें विभिन्न राइड मोड कॉर्नरिंग एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल और एक सुविधाजनक व्हीली कंट्रोल सिस्टम शामिल है।

नई दिल्ली। Ducati India ने Hypermotard 950 RVE को नई कलर स्की के साथ पेश किया है। इसे ग्रैफिटी इवो लिवरली कहा जा रहा है और यह स्ट्रीट आर्ट से इंस्पायर्ड है। ग्रैफिटी ईवो लिवरली की कीमत इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए लगभग 41 हजार रुपये के करीब है। इस तरह इसकी अपडेटेड कीमत 16 लाख रुपये एक्स-शोरूम है।

अपडेटेड Hypermotard 950 RVE में क्या नया?

नई कलर स्कीम की बात करें, तो ये कई स्पलैश-जैसे ग्राफिक्स के साथ आती है, जो मोटरसाइकिल के बॉडी पैनल पर मौजूद हैं। डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950 आरवीई को पावर देने वाला वही 937 सीसी टेस्टास्ट्रेटा एल-ट्विन इंजन है, जो 9000 आरपीएम पर 112 बीएचपी की अधिकतम पावर और 7,250 आरपीएम पर 96 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है।

इसमें थ्रॉटल-बाय-वायर, लिक्विड कूलिंग और डेस्मोड्रोमिक कॉन्फिगरेशन है। ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स एक 6-स्पीड यूनिट है, जो डुकाटी क्विक शिफ्ट के साथ आता है और ये अनिवार्य रूप से एक बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है।

डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950 आरवीई में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्रभावशाली सीरीज है। इसमें विभिन्न राइड मोड, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक सुविधाजनक व्हीली कंट्रोल सिस्टम शामिल है। कई एडवांस फीचर्स हो ने बाद भी ये काफी हल्की बनी हुई है और इसका वजन केवल 193 किलोग्राम है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

हाइपरमोटर्ड 950 आरवीई को मजबूत ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर डेवलप किया गया है। ये पूरी तरह से एडजस्टेबल 45 मिमी मार्जोची यूएसडी फोर्क और प्रीलोड- रिबाउंड डंपिंग एडजेस्टेबिलिटी के साथ आती है।

ये बाइक हाई परफॉरमेंस वाले पिरेली डियाब्लो रोसो III टायरों से लैस 17 इंच अलॉय व्हील से लैस है। ब्रेकिंग पावर फ्रंट में ट्विन 320 मिमी डिस्क द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि पीछे की तरफ विश्वसनीय स्टॉपिंग पावर के लिए 245 मिमी डिस्क है।

एक्टर मनीष पॉल के गैराज में शामिल हुई नई लग्जरी कार, 48.10 लाख रुपये में मिलते हैं ये फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

एक्टर मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर अपनी नई गाड़ी की तस्वीरें भी साझा की हैं। मौजूदा समय में कंट्रीमैन की कीमत 48.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे केवल टॉप-स्पेक कूपर एस जेसीडब्ल्यू इंस्पायर्ड ट्रिम में पेश किया जाता है। MINI Countryman SUV अपनी अंडरपिनिंग्स BMW X1 से साझा करती है। आइए इस लग्जरी कार के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। पॉपुलर एक्टर और टेलीविजन होस्ट Maniesh Paul ने हाल ही में नई MINI Countryman खरीदी है। मनीष पॉल और उनकी उनकी पत्नी संयुक्ता अब मिनी कंट्रीमैन लक्जरी एसयूवी के मालिक हो गए हैं।

कितनी खास है MINI Countryman?

टीवी स्टार ने सोशल मीडिया पर अपनी नई गाड़ी की तस्वीरें भी साझा की हैं। मौजूदा समय में कंट्रीमैन की कीमत 48.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे केवल टॉप-स्पेक कूपर एस जेसीडब्ल्यू इंस्पायर्ड ट्रिम में पेश किया जाता है।

मनीष पॉल ने इंस्टाग्राम पर अपनी मिनी कंट्रीमैन की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन दिया, ₹And our new baby is home !₹ मॉडल को ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन पेंट स्कीम के साथ ब्लैक रूफ में देखा जा सकता है। वहीं इसका बॉटम मिरर कैप और व्हाइट स्ट्रिप्स में मौजूद है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

MINI Countryman SUV अपनी अंडरपिनिंग्स BMW X1 से साझा करती है। इसे पावर देने के लिए 176 बीएचपी और 280 एनएम पीक टॉर्क के लिए ट्यून किए गए 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये पावरट्रेन 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक के साथ आता है। कंट्रीमैन महज 7.5 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

टॉप-स्पेक कंट्रीमैन में नप्पा लेदर से लिपटे स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबिलिटी के साथ सामने बैठे लोगों के लिए स्पोर्ट्स सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 5-इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले सहित कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।

2024 बजाज पल्सर NS400 की पहली झलक आई सामने, डुअल चैनल ABS के साथ मिलेंगे USD फोर्क्स

2024 Bajaj Pulsar NS400 के नवीनतम टीजर से पता चलता है कि मोटरसाइकिल डुअल चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सेफ्टी फीचर के साथ आएगी। एक और चीज जो टीजर से पता चलती है वह है सामने की ओर दिए गए अप-साइड डाउन फोर्क्स। बजाज धीरे-धीरे सभी पल्सर रेंज को फ्रंट में यूएसडी फोर्क्स के लिए अपडेट कर रहा है।

नई दिल्ली। Bajaj Auto 3 मई को अपनी सबसे पावरफुल Pulsar लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई पल्सर के भारतीय बाजार में आने से पहले ब्रांड ने नए टीजर जारी करना शुरू कर दिया है। नई मोटरसाइकिल को Bajaj Pulsar NS400 कहा जाएगा, जिसका मतलब है कि यह मोटरसाइकिलों की NS रेंज में होगी, जो पल्सर की स्पोर्टियर लाइनअप है।

2024 Bajaj Pulsar NS400 में क्या खास?

2024 Bajaj Pulsar NS400 के नवीनतम टीजर से पता चलता है कि मोटरसाइकिल डुअल चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सेफ्टी फीचर के साथ आएगी। हालांकि, इसमें ABS मोड- रेन, रोड और ऑफ/ऑन भी होंगे। एबीएस की बात करें, तो ब्रेकिंग ड्यूटी दोनों सिरों पर डिस्क द्वारा कंट्रोल की जाएगी।

एक और चीज जो टीजर से पता चलती है वह है सामने की ओर दिए गए अप-साइड डाउन फोर्क्स। बजाज धीरे-धीरे सभी पल्सर रेंज को फ्रंट में यूएसडी फोर्क्स के लिए अपडेट कर रहा है। यूएसडी फोर्क्स मोटरसाइकिल को अधिक व्यवस्थित राइड प्रदान करते हैं। Bajaj Pulsar NS400 के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी देगा।

टीजर में एक चीज जो नोटिस की जा सकती है, वह है बॉडी पैनल पर फॉक्स कार्बन फिनिश का इस्तेमाल। पल्सर NS400 का हेडलैंप कुछ हद तक पल्सर NS200 के जैसा ही होगा।

तीसरे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की पैरवी

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

अभी तक सीपीएम के बारे में यह माना जाता था कि वह विचारधारा पर आधारित पार्टी है। लेकिन वह अपने विदेशी स्वभाव के कारण सौ साल बीत जाने पर भी हिंदुस्तान में अपने पैर नहीं जमा सकी। समाप्ति के इस अंतिम चरण में उसने भी किसी न किसी तरह 'सांस चलती रहे' के सूत्र को आधार मान कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है'

पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी देश में घूम-घूम कर बराबर मांग कर रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा सरकार ने जेल भेज दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के इसी प्रकार के आरोपों के कारण केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? राहुल गांधी का कहना है कि विजयन को बिना देर किए तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। राहुल गांधी को गुस्सा और आश्चर्य है कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? वे इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पिनराई विजयन से मिली हुई है। यहां यह बताना जरूरी है कि पिनराई विजयन सीपीएम के नेता हैं और सीपीएम तथाकथित इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। राहुल गांधी के देश के कम्युनिस्टों से कैसे संबंध हैं, इस पृष्ठभूमि में यह जान लेना भी जरूरी है। इसका सामान्य उत्तर तो यही होगा कि बहुत अच्छे हैं।

यह भी कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से तो इतने अच्छे हो गए हैं कि बहुत से कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी में ही चले गए हैं और उन्होंने वहां राहुल गांधी के रथ की कमान ही संभाल रखी है। उनमें से कुछ ने कांग्रेस के नीति पत्र लिखने का काम संभाल लिया है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह देश के सभी लोगों का सर्वे करवाएगी और पता करेगी कि लोगों के पास क्या-क्या है। फिर उसे जरूरतमंदों में रिडिस्ट्रिब्यूट करेगी। अब किन लोगों में करेगी, इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आशंका व्यक्त की है कि कांग्रेस यह पैसा देश में घुस आए अवैध घुसपैठियों में बांट देगी। कांग्रेस का सारा मामला कार्ल मार्क्स वाला बनता जा रहा है।

कम्युनिस्ट भी बहुत खुश थे। सभी रैलियों में वे राहुल गांधी के साथ मंच पर खड़े होकर हाथ लहरा लहरा कर अपनी खुशी का इजहार करते थे। लेकिन इस बीच एक घटना हो गई। राहुल गांधी लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में केरल के वायनाड से खड़े हो गए। कम्युनिस्टों ने संकेतों में उन्हें समझाया भी कि इधर मत आया करो। उधर हिंदी पट्टी से ही चुनाव लड़ा करो। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। वे जानते हैं कि हिंदी पट्टी बहुत तप रही है। वहां चुनाव लडना अब खतरे से खाली नहीं रहा। 2019 की चोट राहुल गांधी भूले नहीं हैं। इसलिए वे फिर वायनाड में दिखाई देने लगे। स्वाभाविक है कम्युनिस्टों को गुस्सा आता और यह गुस्सा आ भी रहा है। जब दो गहरे मित्र लड़ते हैं तो कई बार मामला बहुत बढ़ जाता है और अजीब अजीब रहस्योद्घाटन होने लगते हैं। राहुल गांधी और कम्युनिस्टों के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी ने पिनराई विजयन को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी है। जाहिर है इससे लैफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रंट को भी गुस्सा आता। केरल में सीपीएम ने कुछ दलों को साथ लेकर एलडीएफ यानी लैफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रंट बना रखा है।

मोर्चा ने भी राहुल गांधी को लेकर कुछ मांगें करनी शुरू कर दीं। लेकिन ताज्जुब है कि मोर्चा ऐसी मांगें कर रहा है, जो अपने स्वरूप में राजनीतिक न होकर मौलिक प्रकार की हैं। मोर्चा के एक विधायक पीवी अनवर ने मांग की है कि राहुल गांधी के डीएनए की तुरंत जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल इस देश में चौथे दर्जे के नागरिक हैं और उन्हें अपने नाम से तुरंत गांधी नाम हटा देना चाहिए। अनवर की इस मांग के कारण दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पिनराई विजयन को भ्रष्टाचार के चलते गिरफ्तार करो और मोर्चा कहता है कि राहुल गांधी का डीएनए टैस्ट कराओ। मामला गम्भीर होता देख पत्रकारों के मन में आया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन विजयन तो उससे पहले ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने एक चुनावी सभा में राहुल पर एक बहुत ही गहरा प्रहार किया। इस प्रहार की मारक क्षमता को मध्य काल के हिंदी कवि बिहारी के एक दोहे की सहायता से समझा जा सकता है। बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है, 'देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।'

विजयन का जनसभा में किया गया प्रहार ऊपर से देखने से तो मामूली लगता है, लेकिन घाव बहुत गहरा कर गया है। पूरा सोनिया परिवार मरहम पट्टी करने में व्यस्त है। पिनराई विजयन ने कहा, 'राहुल जी, अतीत में आपको एक नाम से संबोधित किया गया था। अब ऐसी बातें मत करो जिससे लगे कि आप अभी तक वहीं के वहीं खड़े हो।' उस समय तो जनसभा में बैठे बहुत से श्रोता भी नहीं समझ सके कि कामरेड विजयन क्या कह रहे हैं, लेकिन दो-तीन घंटों में ही केरल के चैनलों ने अर्थ समझाना शुरू कर दिया। दरअसल 2011 में केरल के ही उस समय के मुख्यमंत्री कामरेड अच्युतानंदन ने राहुल के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि वह तो 'अमूल बेबी' है। उस समय से केरल में राहुल गांधी को अमूल बेबी कहा जाने लगा था। बाद में उत्तर भारत में राहुल गांधी को पप्पू कहा जाने लगा। सोनिया परिवार के लिए राहुल गांधी के इस तरह के नामों से छुटकारा पाना भी एक राजनीतिक समस्या ही बन गई।

कुछ महीने पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने पूछा था कि इस यात्रा की उपलब्धियां क्या हैं, तो तब प्रियंका ने एक उपलब्धि यह भी बताई थी कि इस यात्रा से लोगों को पता चल गया है कि राहुल अब पप्पू नहीं रहा, उससे बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन अब 2024 में विजयन निराश हैं कि राहुल बौद्धिक स्तर पर अभी भी 2011 में ही रुके हुए हैं, यानी 'अमूल बेबी'। इस सबके बावजूद कांग्रेस और सीपीएम देश भर में सांझी चुनाव रैलियां भी कर रहे हैं। इन रैलियों में राहुल भी होते हैं और सीपीएम के दिग्गज भी। पर धुकधुकी दोनों को लगी रहती है। कामरेड डरे रहते हैं कि कहीं राहुल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की गिरफ्तारी की मांग न कर दें, और कांग्रेस वाले डरे रहते हैं कि कहीं कामरेड राहुल गांधी के डीएनए की जांच की मांग न कर दें। यही हालत पंजाब में है।

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान कहते हैं कि कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। इसके प्रत्याशी को जिताओ। लेकिन दस कदम चलने पर पंजाब आ जाता है। वहां कार से उतर कर वही भगवंत मान चिल्लाते हैं, कांग्रेस से बचो। यह सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है। स्थिति दिन-प्रतिदिन हास्यास्पद होती जा रही है। लेकिन दोनों बराबर डटे हुए हैं कि भाजपा को हराना है। दरअसल आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता को लेकर है। राजनीतिक दल येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाना चाहते हैं। विचारधारा की उनकी दृष्टि में कोई अहमियत नहीं रह गई है। अभी तक सीपीएम के बारे में यह माना जाता था कि वह विचारधारा पर आधारित पार्टी है। लेकिन वह अपने विदेशी स्वभाव के कारण सौ साल बीत जाने पर भी हिंदुस्तान में अपने पैर नहीं जमा सकी। समाप्ति के इस अंतिम चरण में उसने भी किसी न किसी तरह 'सांस चलती रहे' के सूत्र को आधार मान कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है। ऊपर के सभी प्रकरण इसी पृष्ठभूमि में समझे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी यह आरोप लग रहा है कि उसने भी दूसरे दलों के अनेक लोगों को शामिल कर लिया है। लेकिन भाजपा उन लोगों का उपयोग भी अपनी वैचारिक यात्रा को गति प्रदान करने के लिए ही कर रही है। यही कारण है कि आज सब राजनीतिक दल चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के हर काम को क्रियान्वित कर रही है।

संपादक की कलम से

चुनावों की चरागाह में

राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा हर मुख्यमंत्री को कांगड़ा की चुनौतियों के समक्ष खड़ा कर देती हैं और प्रदेश के मौजूदा मुखिया भी इस दौर से गुजर रहे हैं। कांगड़ा की दीवार-कांगड़ा के दीदार और जुल्म की राह पर रार कल थी और आज भी है। कांगड़ा यूं तो सत्ता का एतबार है और राजनीतिक मशक्कत की सफलता का त्योहार है, लेकिन सरकारें बनते ही यह असंतुलित हो रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में यह जिला लाचार, बीमार और शिकार ही साबित हुआ। वाईएस परमार के दौर में पंडित सालिग राम को परास्त करने वाले हों या वीरभद्र सिंह के दौर में मेजर विजय सिंह मनकोटिया के पथ को नष्ट करने वाले नेताओं का कांगड़ी समूह तब भी था। यह धूमल सरकार या जयराम ठाकुर की सत्ता में भी देख गया कि चंद मुद्दे, चंद ख्वाहिशें, चंद नेता और तमाम महत्त्वाकांक्षाओं को किस तरह ठोकरें लगीं। इतिहास में अपने-अपने पतन की कहानी लिख चुके विजय सिंह मनकोटिया या डा. राजन सुशांत की दास्तान का जिक्र अगर अंधे कुओं में होता है, तो यह सफर का रोमांच नहीं, तड़पाने का रास्ता है। कांगड़ा ने अपने ही नेताओं को तड़पते देखा, क्योंकि सदा सत्ता सौंपने वाला जिला एक समूह नहीं बन सका। हर बार लाड़ले वे बने जो नेता बन ही नहीं सकते थे। दो बार मुख्यमंत्री बनकर भी क्या शांता कुमार क्षेत्रीय संवेदना के मुखिया और सियासी ताकत के केंद्र बने। सवाल हमेशा शांता के अधूरे सफर से पूछते रहे, लेकिन डूबा तो यहां का सियासी इतिहास। इसलिए एक बड़ी लावी खड़ी की गई, जो यह तय कर रही थी कि इस भूखंड की राजनीतिक हेकड़ी खत्म करके कैसे परवान चढ़ा जाए।

कांगड़ा के जितने टुकड़े सत्ता को चाहिए वे हर बार हो जाते हैं। कभी जिलों के नाम पर, कभी काम तमाम कर या कभी सत्ता के पदों पर बड़े नेताओं का वजन घटाकर हिमाचल की सरकारें इनसाफ कर रही हैं। पिछली कुछ सरकारों में कांगड़ा को मिले मंत्रिमंडलीय पदों या मंत्रालयों का आबंटन इस तरह हुआ कि राज्य का बजट यहां मुरझा गया। न कोई तहरीर और न ही कोई तकरार, वरना डेढ़ साल की मौजूदा सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल परिसर के तीस करोड़ की शर्त की खिल्ली न उड़ाती। जिस कफन में सो गए अतीत में कई नेता, वह फिर मचान पर खड़ा शिकार गिन रहा। कहां गए रोशन दरवाजे जहां मनकोटिया, सुशांत, किशन कपूर व रमेश धवाला कभी आबाद थे। क्या इस पारी का अंत सुधीर शर्मा की भी यही कहानी लिखेगा। कम से कम जिस तरह की बयानबाजी व आचरण की जोर आजमाइश में शब्दावली बाहर आ रही है, उससे धब्बा तो जरूर लगेगा। वैसे हिमाचल के राजनीतिक संतुलन के लिए शिमला, मंडी और कांगड़ा का अवतार सलामत रहना चाहिए, लेकिन विभाजन के नए संकल्प अब चार संसदीय क्षेत्रों में उपज नहीं बंजरपन उगाना चाहते हैं। सत्ता की उर्वरता इस बार अगर शिमला संसदीय क्षेत्र को सियासत का ग्रीन हाउस बना गई, तो मंडी की वसंत पहले ही चुनावी फलक से शरमा गई है। रही कांगड़ा की हालत, तो यहां हर सत्ता का दोष यही रहा कि कुछ अहम नेता हमेशा हाशिए पर पहुंचा दिए गए। इस बार सत्ता के बीच ही सत्ता के खिलाफ जो जंग हुई, उसके परिणाम में हम या तो नेताओं को बनते या टूटते देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता की टूट कांगड़ा को मिली, बल्कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आरजू भी कहीं धूमिल हुई।

नेताओं की चरागाह में बंजर हुई मर्यादाओं का आलम यह कि कहीं गंगू राम मुसाफिर पल में लौटते, तो अगले पल रोकते हुए मिल जाएंगे। चुनावी रेलगाड़ी में सवार होते डा. राम लाल मार्कंडेय को कांग्रेस की हरी झंडी का इंतजार रहा, लेकिन सुजानपुर में भाजपा की नाव पर रहे रणजीत सिंह ठाकुर अब कांग्रेस के दरिया में कूद पड़े हैं। जनता चाहे तो अचंभित होना छोड़ सकती है क्योंकि सियासत की इत्रदानी में कभी खुशबू हो नहीं सकती। ये चुनाव कुछ नेताओं की बर्बादी का सबब बन सकते हैं, भले ही सियासी बकवास कुछ भी होता रहे।

राय

विरासत कर पर बवंडर

कांग्रेस में छोटे-छोटे टाइम बम होते है। वे जब भी फटते हैं, तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होता है। अमरीका में बसे सत्य नारायण गंगा राम पित्रोदा (सैम पित्रोदा) ऐसे ही बम हैं। वह कई संवेदनशील और राष्ट्रीय घटनाओं पर अनाप-शनाप बोलते रहे हैं। वह 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' के अध्यक्ष हैं। जब भी केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी है, उसमें उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मनमोहन सरकार में ही वह 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' के अध्यक्ष थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार थे और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार में उनका योगदान अहम रहा है। वह पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र लिखने वालों में एक रहे हैं। आजकल सैम पित्रोदा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार और रणनीतिकार हैं। यदि ऐसा शख्स, भारत के संदर्भ में, कोई बयान या परामर्श देता है, तो वह उसका 'निजी' कैसे हो सकता है? कांग्रेस अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है? सैम ने अमरीका के 6 राज्यों में लागू 'इंहेरिटेंस टैक्स' (विरासत कर) का उल्लेख किया है कि अमरीकी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति का 45 फीसदी हिस्सा बच्चों, परिजनों को मिलता है। शेष 55 फीसदी सरकार ले लेती है। यह कानून एक निश्चित आय के वर्ग पर ही लागू होता है। अमरीका के अलावा जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया आदि देशों में भी विरासत-कर की व्यवस्था है। वे देश जनता और समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व मानते हैं, लिहाजा उसकी संपत्ति में सामाजिक-सार्वजनिक हिस्सेदारी भी मानी जाती है।

भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लिहाजा सैम पित्रोदा का सुझाव था कि भारत में भी इस विषय पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा-एनडीए ने तुरंत इस मुद्दे को भी लपक लिया। प्रधानमंत्री ने यहां तक टिप्पणी की कि कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। निजी संपत्तियों को छीन कर उन्हें एक समुदाय विशेष में बांटने का मुद्दा बेहद उग्र हो रहा था, 'विरासत-कर' पर भी बवंडर छिड़ गया है। अब चुनाव की दिशा और लहर ही बदल गई हैं। भारत में 1953 से 1985 तक एक कानून लागू था-'एस्टेट ड्यूटी एक्ट।' उसके तहत 20 लाख रुपए या अधिक की संपत्ति पर 85 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था। वह विरासत-कर का ही एक रूप था। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस कर को निरस्त किया, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के वित्त मंत्री इस कर की पैरवी करते रहे। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेतली ने 2018 में कहा था कि विरासत-कर से विदेशों में अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को वित्तीय अनुदान मिलते रहे हैं, लिहाजा इस कर पर विमर्श किया जाना चाहिए। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट के दौरान 'इंहेरिटेंस टैक्स' का उल्लेख किया था। फिलहाल भारत में इस कर-व्यवस्था के प्रावधान नहीं हैं। किसी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह एजेंडा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार आई, तो 'विरासत-कर' लगाएगी। आपके मकान-दुकान, खेत, जमीन और धन, सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपके बच्चों और परिजनों का 'पैतृक संपत्ति' में हिस्सा आंशिक रह जाएगा।

क्या आप ऐसा होने देंगे? हालांकि लोगों की संपत्ति के सर्वे वाले बयान पर राहुल गांधी ने अब यह कहा है कि वह जानना चाहते हैं कि देश में कितना अन्याय है। उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वह 'वेल्थ सर्वे' कराएंगे। कानूनन यह संभव नहीं है। उद्योगपतियों पर 'वेल्थ टैक्स' 2015 के बजट में ही हटा लिया गया था।

हंसराज ठाकुर

विश्व शतरंज में नई भारतीय चुनौती

शतरंज के खेल में दोम्माराजू गुकेश की इस सफलता से युवा शतरंज खेल की तरफ आकर्षित होंगे। शतरंज खेल को गंभीरता से लेने वाले कई देशों में, यह बात भी उभर कर सामने आई है कि बौद्धिक क्षमता उत्सर्जन वाले इस खेल से जुड़ने वाले युवा पढ़ाई के क्षेत्र में भी अव्वल पाए गए'

भारतीय शतरंज के उभरते युवा सितारे दोम्माराजू गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई (तमिलनाडु) में हुआ। मार्च 2019 में दोम्माराजू गुकेश विश्व शतरंज के इतिहास में ग्रैंड मास्टर बनने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी रहे। फीडे विश्व रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी भी बन चुके हैं। विश्व कप के दौरान दोम्माराजू गुकेश ने मिस्टराडिन इस्कंदरोव को हराकर 2755.9 की लाईव रेटिंग प्राप्त की। फिर 2758 सितंबर 2023 में इनकी शीर्ष रेटिंग रही। अब 2763 के करीब आने वाली है और विश्व क्लासिकल ओपन वर्ग में नौवें स्थान पर पहुंचे, जबकि विश्वनाथन आनंद 2754 की रेटिंग के साथ दसवें स्थान पर थे। गुकेश ने 17.17 वर्ष की सबसे कम उम्र में 2750 की ईलो रेटिंग पार करने का मैग्नस कार्लसन का 17.34 वर्ष का रिकॉर्ड तोडक़र, पहली बार भारतीयों के नाम किया। फीडे सर्किट सर्कल में शीर्ष स्थान पर रहने वाले दोम्माराजू गुकेश ने इसी बूते वर्ष 2024 में टोरोंटो में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।

तेजी से उभरते इस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी से हर भारतीय शतरंज प्रेमी को, भारतीय शतरंज के उज्ज्वल भविष्य के प्रति बहुत उम्मीदें हैं। गुकेश ने वर्ष 2015 में एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप और अंडर-12 आयु वर्ग में वर्ष 2018 में विश्व युवा शतरंज चैम्पियनशिप का अंडर-9 वर्ग जीता। अंडर-12 व्यक्तिगत रैपिड और ब्लीट्ज, अंडर-12 टीम रैपिड ओर ब्लीट्ज तथा अंडर-12 क्लासिकल शतरंज के प्रारूप में, वर्ष 2018 एशियाई यूथ शतरंज चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रौशन किया। एशियाई व चेस ओलिंपियाड खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के पहले व विश्व के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। फीडे स्वर्ण जयंती वर्ष 2024 में प्रायोजित फीडे कैंडिडेट प्रतियोगिता 3 अप्रैल से 23 अप्रैल तक टोरोंटो में आयोजित हुई। 14 दौर की बाजियां डबल राउंड रोबिन के आधार पर खेली गईं। पूरे विश्व की नजरें कैंडिडेट्स के विजेता पर लगातार बनी रही। पहली बार कैंडिडेट्स ओपन वर्ग के इतिहास में तीन भारतीय युवा शतरंज सितारों ने दस्तक दी और महिला वर्ग में दो भारतीय महिला प्रतिभागियों ने शिरकत की। बेशक कैंडिडेट प्रतियोगिता के शुरुआती चरण में भारतीय युवाओं को नवोदित खिलाडियों के रूप में देखा जा रहा था, मगर जैसे जैसे यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, सभी भारतीय खिलाड़ी अपनी छाप विश्व शतरंज पटल पर छोड़ते गए। अभी तक मात्र विश्वनाथन आनंद ही कैंडिडेट्स तक पहुंच कर, कई बार विभिन्न शतरंज खेल प्रारूपों में विश्व चैंपियन बने। मगर फीडे के आधिकारिक सौवें साल में एक नया भारतीय सितारा विश्व शतरंज प्रेमियों को देखने को मिला। भारत के लिए ये लम्हे गर्वित करने वाले हैं कि 17 वर्षीय दोम्माराजू गुकेश विश्व शतरंज कैंडिडेट के इतिहास में सबसे युवा विजेता खिलाड़ी बने।

डी. गुकेश दूसरे भारतीय व विश्व के प्रथम युवा खिलाड़ी बने कैंडिडेट्स प्रतियोगिता को जीतकर। विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के चैलेंजर भी बने। डी. गुकेश ने 40 वर्ष पुराने इतिहास को बदल कर एक नया इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के दौरान डी. गुकेश ने अपनी 14 दौर की बाजियों में पहली बाजी भारतीय खिलाड़ी विदित गुजराती से ड्रॉ खेली। दूसरी बाजी भारत के एक और युवा सनसनी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा से जीती। तीसरे दौर की बाजी में पूर्व दो बार के कैंडिडेट्स विजेता इयान नेपोमिनियाची को बराबरी पर रोका। चौथी बाजी अमरीका के फाबियानो कारूआना के साथ बराबरी पर रोकी। पांचवें दौर में गुकेश ने निजत अबासोव को हराकर विजय प्राप्त की। छठे दौर में अमरीका के हिकारू नाकामुरा को बराबरी पर रोकते हुए ड्रॉ खेला। मात्र एक हार गुकेश को प्रतियोगिता के सातवें दौर की बाजी में अलीरेजा फिरोजा से मिली। इसके बाद इस युवा खिलाड़ी ने आठवें दौर की बाजी में विदित गुजराती को हरा दिया। नवें दौर की बाजी भारतीय सनसनी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा से ड्रॉ की। दसवें दौर की बाजी भी इयान नेपोमिनियाची से ड्रॉ खेली। ग्यारहवें दौर की बाजी फाबियानो कारूआना से ड्रॉ की। बारहवें दौर में पुनः निजत अबासोव को हराकर विजय प्राप्त की और 13वें दौर की बाजी में अपनी हार का बदला लेते हुए अलीरेजा फिरोजा को हराकर शीर्ष बढ़त कायम कर ली। अंतिम व चौदहवें दौर में हिकारू नाकामुरा को बराबरी पर रोकते हुए नौ अंक अर्जित करके प्रतियोगिता के निर्विवाद विजेता बने।

हालांकि सभी भारतीयों ने ओपन वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया और कई बड़े उलटफेर करते हुए विश्व शतरंज जगत को चकित किया। भारत से जन्मे इस खेल में पुनः भारत शीर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं महिला वर्ग में पहली बार दो भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी व आर. वैशाली ने शिरकत करते हुए, अपने शानदार खेल से विश्व जगत को चकित किया और संयुक्त रूप से प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहीं। एक बात इस कैंडिडेट्स प्रतियोगिता से स्पष्ट सामने आई है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए तो परिणाम हमेशा सार्थक ही आएंगे।

अतः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भारतीय शतरंज महासंघ व सभी राज्य संघों को बुनियादी स्तर पर अधिक सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है। युवाओं में सीखने की क्षमता वयस्कों से कहीं अधिक भी हो सकती है। शतरंज के खेल में दोम्माराजू गुकेश की इस सफलता से निश्चित रूप से युवा शतरंज खेल की तरफ अधिक आकर्षित होंगे। शतरंज खेल को गंभीरता से लेने वाले कई देशों में, यह बात भी उभर कर सामने आई है कि बौद्धिक क्षमता उत्सर्जन वाले इस खेल से जुड़ने वाले युवा अक्सर पढ़ाई के क्षेत्र में भी अव्वल पाए गए। यदि सभी भारतीय राज्य शतरंज संघ व अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ईमानदारी से विषय की गंभीरता को समझें और देश तथा प्रदेश की सभी प्रादेशिक सरकारें भी यह बात समझें, तो भारत हमेशा से ही शतरंज का जन्मदाता और शीर्ष नेतृत्वकर्ता देश बनकर, विश्व पटल पर बना रहेगा और शतरंज में सकारात्मक माहौल बनेगा।

पूरन सरमा

गरीब को उठाना है...

देश के तमाम राजनेता इस बात पर एक मत हैं कि गरीबों को उठाना है। नेताजी मिले तो मैंने कहा, क्यों साहब, यह तो आप लोग अपने भाषणों में आम तौर पर कहा करते हैं कि गरीब को उठाना है, तो इसका तात्पर्य क्या है? 'गरीबों को उठाने का मतलब गरीबी मिटाने से है। इन्हें उठाए बगैर गरीबी नहीं मिट सकती।' 'तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि गरीबी को उठाकर इस देश से बाहर समंदर में डाल देना है, या उसे चार कंधे देने हैं अथवा उसका वोट हथियाना है, गरीब आदमी तो वैसे ही आपको वोट देने को विवश है।' 'इसीलिए तो उसे उठाना है, मेरा मतलब यह है कि वह हमें वोट दे तो क्या हम खुशी में पागल होकर उसे शाबाशी रूप में भी नहीं उठा सकते। जब तक लोकतंत्र है तब तक गरीब को उठाया जाता रहेगा।' वह बोला। मैंने कहा, 'यह ठीक है कि गरीब को उठाना है, परंतु आपके पास गरीबी के अलावा भी कोई विषय है, जिस पर बातचीत की जा सकती है?' 'गरीबी ही देश की एकमात्र ज्वलंत समस्या है। गरीबों के देश में अमीरों की बात करना भी तो उचित नहीं है। उसमें पूंजीवादी, असमाजवादी तथा अलोकतांत्रिक होने की तोहमत लग सकती है। इसलिए प्यारे भाई, गरीबों के मुल्क में हमें गरीबी से सरोकार रखना ही पड़ेगा।' उसका जवाब था। 'दरअसल आपका फरमाना वाजिब है।

देश में बढ़ती महंगाई ने गरीब की कमर तोडक़र रख दी है। इसीलिए वह बुरी तरह गिर पड़ा है। ऐसे में भी यदि वह गिरा रह गया तो गिरा माना जाएगा। भारतीय गरीब की मौलिक पहचान गरीब होते हुए भी खड़े रहना है। वह इतना गिरा हुआ गरीब नहीं है कि गिरा हुआ ही रह जाए।' मेरी इस बात पर नेताजी हिनहिनाए, 'अरे अब समझे गरीबों के सरदार तुम मर्म की बात। गरीब को न तो आराम करने देना है और न सोने देना है। उसे अपनी गरीबी के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहना है, अतः उसका हाथ पर हाथ धरे रहना ठीक नहीं है, इस दृष्टि से भी बैठे हुए गरीब की सही पहचान यही है कि वह निरंतर मेहनत-मशक्कत करता रहे। इससे सरकार को पता रहता है कि कौन गरीब है अथवा कौन अमीर है। यदि गरीब को अपने को उठाना है तो यह आभास निरंतर कराना होगा कि वह आराम से बैठा हुआ नहीं है।' 'वाकई बात तो नेताजी आपने मार्के की कही है। परंतु क्या इस देश में गरीबी का उन्मूलन कभी संभव भी होगा?' मैंने शंका रखी। 'तुम्हें तमीज कब आएगी?

यह देश गरीब है, इसकी यही पहचान है। यदि गरीबी मिट गई तो गरीब उठाने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जन-सेवा का क्या होगा? इसलिए गरीबों के मुल्क में गरीबी का अस्तित्व तब तक जरूरी है- जब तक यह वर्तमान समाजवादी, कल्याणकारी सरकार मौजूद है। जो लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं- वे गरीबी के दुश्मन हैं। गरीबी मिटानी नहीं, उठानी है, यानी बढ़ानी है। तभी यह संख्या में ज्यादा होंगे तथा देश का नाम रोशन होगा।' नेताजी ने फिर वक्तव्य बदला।

इनसाइड

PF खाते में कब तक आएगी ब्याज की रकम, EPFO ने पोस्ट देकर खुद दिया जवाब

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के यूजर पीएफ इंटरेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफ इंटरेस्ट को लेकर ईपीएफओ ने अपडेट दिया है। ईपीएफओ ने बताया कि वह पीएफ अकाउंट में किस दिन इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। चलिए जानते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि पीएफ अकाउंट (PF Account) में ब्याज आया है या नहीं।

नई दिल्ली। इस साल पीएफ यूजर्स को सरकार ने खुशखबरी दी। सरकार ने ईपीएफ के ब्याज दर (EPF interest rate hiked) में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद अब यूजर पीएफ अकाउंट (PF Account) में ब्याज के क्रेडिट (EPF Interest Rates Credit) होने का इंतजार कर रहे हैं।

इसको लेकर कई यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ईपीएफओ (EPFO) से सवाल भी पूछा कि पीएफ का ब्याज (PF Interest Rates) किस दिन क्रेडिट होगा। ईपीएफओ ने यूजर के सवालों का जवाब दिया। ईपीएफओ ने बताया कि ब्याज दर क्रेडिट करने का काम चल रहा है। जल्द ही 8 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट में ब्याज दर आ जाएंगे।

ईपीएफ यूजर आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चेक कर सकते हैं कि उनके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है या नहीं।

Q4 में 45 प्रतिशत बढ़ा इस सरकारी बैंक का मुनाफा, डिविडेंड का भी किया एलान, शेयरों पर रखें नजर

परिवहन विशेष न्यूज

पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। बैंक के नेट प्रॉफिट में 45 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1.40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी एलान किया है। बोर्ड ने FPO या राइट्स इश्यू जैसे किसी मोड से 7500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की भी मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली। सरकार के मालिकाना हक वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) के नेट प्रॉफिट में मार्च तिमाही में 45 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है। बैंक ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को जारी रिजल्ट में बताया कि बैड लोन में कमी और ब्याज से कमाई में इजाफे से उसे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।

वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (Q4) में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1,218 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो एक साल पहले 840 करोड़ रुपये था। बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि तिमाही के दौरान उसकी कुल इनकम भी 5,317 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,488 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इंटरेस्ट इनकम में भी जोरदार उछाल दिखा। यह 5,467 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 4,495 करोड़ रुपये थी।

डिविडेंड का भी एलान

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1.40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी एलान किया है। अगर एसेट क्वॉलिटी की बात करें, तो बैंक का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) मार्च 2023 के अंत तक 2.47 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2024 तक ग्रॉस एडवांस का 1.88 प्रतिशत हो गईं। वहीं, नेट NPA भी 0.25 से घटकर 0.20 प्रतिशत पर आ गया।

बैड लोन में आई कमी

बैड लोन रेशियो में गिरावट ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (Q4FY24) के लिए NPA प्रोविजिनिंग को घटाकर 457 करोड़ रुपये करने में मदद की। एक साल पहले यह 545 करोड़ रुपये था। 30 मार्च, 2024 तक बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो 98.34 प्रतिशत था। हालांकि, वित्त वर्ष 2023 के अंत में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (capital adequacy ratio) 18.07 प्रतिशत से घटकर 17.38 प्रतिशत पर आ गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) या राइट्स इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) इश्यू, या किसी अन्य मोड से 7,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने को भी मंजूरी दे दी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर (Bank of Maharashtra Share Price) शुक्रवार (16 अप्रैल) को करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 67.75 रुपये बंद हुए। इसने पिछले 6 महीने में 60 प्रतिशत और 1 साल में 128 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने के दौरान भी बैंक के शेयरों में करीब 15 प्रतिशत की तेजी आई है।

चुनावी माहौल में एयर इंडिया एक्सप्रेस लाई खास ऑफर, इन वोटर्स को एयरलाइन दे रही है सस्ती टिकट

देश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए मतदान शुरू हो गया है। लोग वोट देने के लिए अपने शहर के लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने वोटर्स के लिए खास ऑफर निकाला है। एयरलाइन ने ,VoteAsYouAre कैंपेन के तहत यह ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर का लाभ फर्स्ट टाइम वोटर्स को मिलेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस बार 7 चरणों में वोटिंग होगी। आज 13 राज्य में वोटिंग हो रही है। वोटिंग देने के लिए कई मतदाता अपने शहर भी जा रहे हैं।

सभी मतदाता वोट दे इसके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) एक खास ऑफर लेकर आया है। इसमें जो भी वोटर पहली बार वोट दे रहे हैं यानी फर्स्ट टाइम वोटर को एयर टिकट बुकिंग पर 19 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

एयरलाइन ने यह ऑफर #VoteAsYouAre कैंपेन के तहत शुरू किया है।

क्या है एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफर

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि #VoteAsYouAre कैंपेन के साथ कनेक्शन बनाई है। एयरलाइन युवाओं को वोट देने में मदद कर रहा है जिससे 'न्यू इंडिया के स्मार्ट कनेक्टर' की स्थिति में मजबूती आ रही है।

एयरलाइन न यह ऑफर युवा वोटर्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। इस आम चुनाव में लगभग 130 मिलिनियन वोटर्स है, जिनकी आयु 18 से 23 साल के बीच है।

वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय स्टार्टअप्स ने फाइल किए 83 हजार पेटेंट

2022-23 के दौरान भारतीय स्टार्टअप्स ने 83 हजार पेटेंट फाइल किए हैं और वार्षिक आधार पर इसमें 24 .6 प्रतिशत की वृद्धि रही है। नैस्काम की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बीते दो दशक के दौरान पेटेंट फाइलिंग में यह सबसे ज्यादा वृद्धि रही है। 15 मार्च 2023 से 14 मार्च 2024 के दौरान एक लाख से ज्यादा पेटेंट आवंटित किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय स्टार्टअप्स ने 83 हजार पेटेंट फाइल किए हैं और वार्षिक आधार पर इसमें 24.6 प्रतिशत की वृद्धि रही है। नैस्काम की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते दो दशक के दौरान पेटेंट फाइलिंग में यह सबसे ज्यादा वृद्धि रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) और न्यूरो टेक्नोलाजी से जुड़े स्टार्टअप पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष पर रहे हैं। वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान पेटेंट आवंटन में दोगुना की वृद्धि रही है और इसमें आगे भी महत्वपूर्ण वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

15 मार्च 2023 से 14 मार्च 2024 के दौरान एक लाख से ज्यादा पेटेंट आवंटित किए जा चुके हैं। नैस्काम के प्रेसिडेंट देबजानी घोष के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि भारत की बढ़ती नवाचार क्षमता का स्पष्ट संकेत है।

ट्रेनों में तत्काल टिकट ऐसे करें बुक, कन्फर्म टिकट की होगी गारंटी

गर्मी की छुट्टियों में रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में कई लोग घूमने के लिए पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। वहीं कई बार लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से लोग तत्तकाल टिकट बुकिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप आसानी से कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। गर्मी की छुट्टियां हों या फिर शादी-त्योहार का सीजन अक्सर हमें रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिलती है। ट्रेन में सफर करने के लिए लोग महीनों पहले ही कंफर्म टिकट बुक कर देते हैं।

अगर टिकट की बुकिंग करते समय हमें लंबी वेटिंग लिस्ट शो होती है तब टिकट के कंफर्म होने के चांस काफी कम हो जाती है। ऐसे में लोग कन्फर्म टिकट के लिए तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) के ऑप्शन को चुनते हैं।

कंफर्म टिकट के लिए तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की जाती है पर कुछ समय होने की वजह से उसमें भी कन्फर्म टिकट नहीं मिलती है। तत्काल टिकट बुक (Tatkal Ticket Booking) करना आसान नहीं है। कुछ समय के लिए ही तत्काल टिकट का विंडो ओपन होता है ऐसे में नेट की दिक्कत या फिर स्लो सर्वर की वजह से टिकट बुक नहीं हो पाती है।

आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आसानी से तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है।

कैसे करें कन्फर्म तत्काल टिकट बुक (How to book confirm tatkal ticket)

- तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या फिर ऐप पर अकाउंट बनाकर लॉग-इन करना होगा।
- इसके बाद आप 'My Account' पर क्लिक करें।
- अब आपको मास्टर लिस्ट के ऑप्शन में जाकर पैसेंजर्स की सभी जरूरी जानकारी को ऐड करना होगा।

एक बार पैसेंजर्स की जानकारी देने के बाद आपको दोबारा यह जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेल्स ले लेगा।

- अब जब तत्काल टिकट की विंडो ओपन होगी उस समय आपको अपने ट्रैवल डिटेल्स देनी होगी।
- इसके बाद मास्टर लिस्ट में मौजूद जानकारी अपने आप आ जाएगी और आपका समय बच जाएगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के मुरीद हुए S&P और Fitch , कहा- कंपनी को इस बात का होगा

भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ( ) को वैश्विक रेटिंग एजेंसी SP और Fitch से सराहना मिली है। मार्च तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर एजेंसी ने कहा कि अगली तिमाही में कंपनी के EBITDA में तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी द्वारा निवेश पर भी रेटिंग एजेंसी ने प्रतिक्रिया दी।

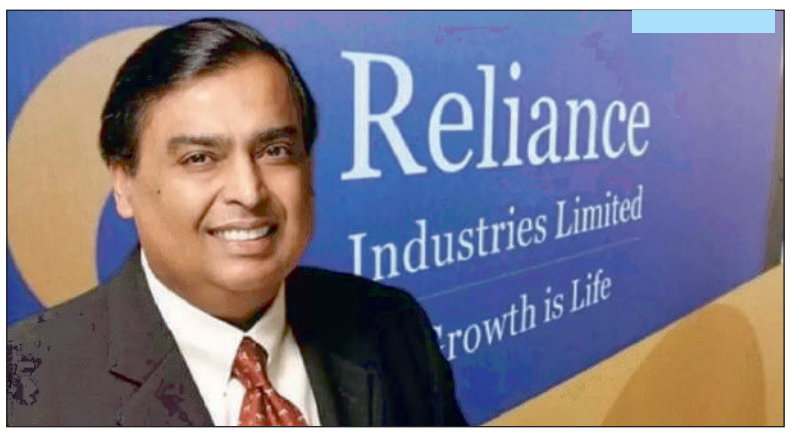

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री (Reliance Industries) को वैश्विक रेटिंग एजेंसियों एसएंडपी (S&P) और फिच (Fitch) से सराहना मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को लेकर जारी नतीजों पर एजेंसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और फिच रेटिंग्स ने अलग-अलग नोटों में चालू वित्त वर्ष और अगले राजस्व और पिछले निवेशों के कारण इसके EBITDA (जिसे कर-पूर्व लाभ के रूप में जाना जाता है) के बढ़ने की बात कही है।

कंपनी बढ़ा रही है निवेश

- इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने द वॉल्ट डिज़नी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेन्चोर (JV) साइन किया। मीडिया सेक्टर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आरआईएल 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। कंपनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क Viacom18 Media Pte Ltd
- 2024 में, इसने एक मीडिया संयुक्त उद्यम के लिए द वॉल्ट डिज़नी कंपनी के साथ बाध्यकारी निश्चित समझौते में प्रवेश किया, जिसमें आरआईएल 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके बाद कंपनी स्थानीय मनोरंजन नेटवर्क Viacom18 Media Pte Ltd में पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 4,300 करोड़ रुपये में खरीदने पर सहमत हुई।
- कंपनी को 2024 में बंगाल की खाड़ी में KG-D6 ब्लॉक में गैस भंडार विकसित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली। इससे कंपनी की गैस उत्पादन क्षमता 13-17 फीसदी तक बढ़ सकती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले ही घोषणा कर दी कि वह तेल-से-रसायन व्यवसाय के लिए पांच वर्षों (2022 से शुरू) में 75,000 करोड़ रुपये के विस्तार की योजना बना रहे हैं।

RBI के एक्शन का कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या होगा असर, उबरने में लगेगा कितना वक्त?

बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कोटक महिंद्रा बैंक को बड़ा झटका दिया। उसने प्राइवेट सेक्टर के इस बड़े बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी। इससे बैंक की क्रेडिट ग्रोथ और मुनाफे पर काफी बुरा असर पड़ने का अनुमान है। आइए जानते हैं कि बैंक को इस झटके से उबरने में कितना वक्त लग सकता है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। बैंकिंग रेगुलेटर ने कोटक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने से भी रोक दिया।

अमेरिका की प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी- S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई के रेगुलेटरी एक्शन का व्यापक असर होगा। इससे बैंक की क्रेडिट ग्रोथ के साथ मुनाफा भी घट सकता है। कोटक के लिए क्रेडिट कार्ड सेगमेंट कमाई का बड़ा जरिया है। अमेरिकी एजेंसी का कहना है कि इसमें 31 दिसंबर 2023 तक सालाना आधार पर 52 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। वहीं, टोटल लोन सिर्फ 19 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

अब क्या करेगा कोटक महिंद्रा बैंक

S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। उसे अपनी फिजिकल ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके।

लेकिन, इसमें मसला यह है कि फिजिकल ब्रांच को ऑपरेट करने की लागत काफी अधिक होती है।

हालांकि, हालिया घटनाक्रम के चलते कोटक महिंद्रा बैंक की रेटिंग पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। S&P ने इसे 'स्टेबल' पर बरकरार रखी है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बैंक के टोटल लोन में क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी महज 4 फीसदी है। यह अभी भी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को मौजूदा ग्राहकों को बेचकर अच्छी कमाई कर सकता है।

कब तक उबर पाएगा कोटक?

S&P का मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक को RBI की मुख्य शिकायतें दूर करने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है। इसमें सिस्टम स्टेबिलिटी, पैच मैनेजमेंट और डिजास्टर रिकवरी शामिल हैं। RBI इससे पहले भी कई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर इसी तरह का एक्शन ले चुका है।

RBI ने साल 2020 में HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर जोड़ने पर अस्थायी रोक लगाई थी। बैंक को आरबीआई की शर्तें पूरी करने और प्रतिबंध हटवाने में एक साल लग गए थे।

केंद्रीय कर्मचारी DA को लेकर हैं कन्फ्यूज, शून्य हुआ या 54% मिलेगा महंगाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले महंगाई भत्ते में साल भर में दो बार बढ़ोतरी होती है। इस साल एक बार महंगाई भत्ते में इजाफा (DA Hike) 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। अब जुलाई 2024 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारी कन्फ्यूज हैं कि उनका डीए कितना बढ़ेगा। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर महंगाई भत्ते को लेकर यह कन्फ्यूजन क्यों हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा (DA Hike) किया है। इस इजाफा के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया है। इसके बाद महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया है।

डीए हाइक के बाद भी कर्मचारी काफी कन्फ्यूज हैं। दरअसल, सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ता का डेटा अपडेट नहीं किया है। जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसदी पर पहुंचता है तो इसे शून्य (0) करने का नियम है।

ये नियम 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के समय बनाया गया था। अब यह नियम लागू हुआ है या नहीं इसको लेकर को अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

महंगाई भत्ता में हुए इजाफे के बाद कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डीए शून्य हो जाएगा। हालांकि, अभी तक लेबर ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स के डेटा को जारी नहीं किया है। वैसे तो महंगाई भत्ते (dearness allowance) की कैलकुलेशन डेटा 28 मार्च 2024 को रिलीज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये डेटा जारी नहीं होने की वजह से दो स्थिति बन रही।

कई लोग मान रहे हैं कि लेबर ब्यूरो ने महंगाई भत्ते को कैलकुलेशन में बदलाव किया है तो कुछ का मानना है कि इन महंगाई भत्ते को कैलकुलेशन पुरानी तरह से ही होगा।

महंगाई भत्ता रिपोर्ट नहीं हुआ जारी

कर्मचारियों (Central government employees) के लिए अब जुलाई में महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाया जाएगा। AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार डीए 50.84 फीसदी हो गया। AICPI इंडेक्स के आंकड़े जनवरी 2024 में जारी किये गए थे। फरवरी 2024 के लिए लेबर ब्यूरो ने डेटा जारी नहीं किया है।

ऐसे में केवल उम्मीद ही लगाई जा रही है कि डीए शून्य हो सकता है। किसी भी तरह के डेटा जारी न होने की वजह से कर्मचारियों को पता नहीं चल पा रहा है कि डीए कितना बढ़ेगा।

'व्यवस्था पर आंख मूंदकर शक करना गलत', वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही अहम बात

परिवहन विशेष न्यूज

पीठ ने कहा कि 'संतुलित परिपेक्ष महत्वपूर्ण है। आंख मूंदकर किसी भी व्यवस्था पर संदेह करना उस व्यवस्था के प्रति शक पैदा कर सकता है। सार्थक आलोचना करने की जरूरत है फिर चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर विधायिका।'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम के वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी मिलान संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि किसी भी प्रणाली पर आंख मूंदकर संदेह करना किसी भी व्यवस्था के प्रति शक पैदा कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए ये निर्देश

पीठ ने कहा कि 'संतुलित परिपेक्ष महत्वपूर्ण है। आंख मूंदकर किसी भी व्यवस्था पर संदेह करना उस व्यवस्था के प्रति शक पैदा कर सकता है। सार्थक आलोचना करने की जरूरत है फिर चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर विधायिका। लोकतंत्र, सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास कायम रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम संबंधी याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही चुनाव आयोग के लिए भी दो निर्देश जारी किए हैं। जिसके पहले निर्देश के तहत कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ईवीएम में चुनाव चिन्ह लोड करने के बाद चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को सील करके सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। इन सील कंटेनर्स को चुनाव नतीजे घोषित होने के 45 दिन बाद तक ईवीएम के साथ ही सुरक्षित स्टोर रूम में रखना चाहिए।

उम्मीदवारों की लिखित मांग पर जांची जा सकेगी ईवीएम

अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि निर्वाचन सीट पर चुनाव के बाद पांच प्रतिशत ईवीएम मशीनों, जिनमें ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट भी शामिल हो, उनके इस्तेमाल हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर्स, ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा चेक किए जाएं। दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवारों की लिखित मांग पर जांच हो सकती है। चुनाव नतीजे घोषित होने के सात दिनों के भीतर यह मांग की जा सकती है। जांच की मांग करने वाले उम्मीदवार को ही इसकी लागत वहन करनी होगी और अगर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप सही साबित हुआ तो चुनाव आयोग को उम्मीदवार को लागत के पैसे लौटाने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने और ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी मिलान करने की मांग की गई थी। अभी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान हर सीट पर किन्हीं भी पांच ईवीएम मशीनों के साथ ही किया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव को नियंत्रित करने वाली अथॉरिटी नहीं हैं और न ही एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को आदेश दे सकते हैं। एनजीओ एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा कि 'आप पहले से ही मन बना चुके हैं तो हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहां आपकी सोचने की प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं हैं।'

कर्मचारी नेता का दावा- CM ने फाइल पर साइन करने में की देरी, MSRTC की 2200 बसें खरीदने की योजना रुकी

परिवहन विशेष न्यूज

अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के श्रीरंग बर्गे ने कहा कि एमएसआरटीसी के बेड़े की 15,600 में से 10,000 बसें दयनीय स्थिति में हैं। फाइल पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण गर्मियों में वाहनों की कमी हो गई है।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी संघ के एक नेता ने गुरुवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण 2,200 बसें खरीदने की योजना रुक गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 15,600 में से 10 हजार बसें दयनीय हालत में हैं।

अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के श्रीरंग बर्गे ने कांग्रेस के तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, एमएसआरटीसी के बेड़े की 15,600 में से 10,000 बसें दयनीय स्थिति में हैं। फाइल पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण गर्मियों में वाहनों की कमी हो गई है। बर्गे ने कहा, बेड़े की कई बसें 8.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी हैं। ये बसें बार-बार ब्रेकडाउन से ग्रस्त हैं, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों को असुविधा होती है। इसके अलावा, ऐसी बसों के कारण एमएसआरटीसी की परिचालन लागत में 1.5 फीसदी वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने फंड से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए 2,200 बसों की खरीद रोक दी गई है। फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया? इसे लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से काफी पहले मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था। बर्गे ने कहा कि एमएसआरटीसी के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री को इस देरी के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर दिए जाने के बाद नई बसों को आने में कम से कम तीन महीने लगते हैं।

एमएसआरटीसी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी से 5,150 ई-बसें किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किया था। इसके मुताबिक उसे हर महीने 215 बसों की आपूर्ति की जानी थी। लेकिन अब तक केवल 20 मध्यम आकार के वाहन ही आए हैं।

स्वीपर के पद पर जर्नल कैटेगरी की भर्ती का विरोध

परिवहन विशेष। एसडी सेठी

पंजाब नेशनल बैंक में स्वीपर के पद पर जनरल कैटेगरी के लोगों की भर्ती किए जाने पर आल इंडिया पीएनबी एससी/एसटी-इम्पलाइज वेल्फयर एसोसिएशन (दिल्ली) ने अपना विरोध जताया है। एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दुली चंद के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक में स्वीपर/पीटीएस के पद पर एससी/एसटी कोटे के कैंडीडेट को दरकिनार कर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती कर दिया है। अब आलम ये है कि जनरल कैटेगरी से भर्ती सफाई कर्मचारी/पीटीएस टॉयलेट,गंदगी की सफाई तक नहीं करते है। उन्होंने बाकायदा टॉयलेट, गंदगी सफाई/या गंदगी उठाने के लिए बाहरी स्वीपर को रख लिया है। उनसे वह टॉयलेट आदि की सफाई का काम लेते हैं। इसके लिए जनरल कैटेगरी के भर्ती स्टाफ अपनी जेब से बाकायदा पेमेंट करते हैं। इस बाबत जोनल सेकेट्री ऑल इंडिया पीएनबी एससी/एसटी इम्पलाइज एसोसिएशन (दिल्ली) के अध्यक्ष दुली चंद ने दिल्ली के द्वारका स्थित पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन, को बाकायदा दिनांक 12 मार्च, 2023 को पत्र लिखकर एससी/एसटी वर्ग पीटीएस पर हो रहे अत्याचार से अवगत कराया जा चुका है। इस पत्र की कॉपी बाकायदा राष्ट्रीय सफाई आयोग ,मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, समेत बैंक के विजिलेंस विभाग तक को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष दुली चंद के मुताबिक 15 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कारवाई करने की जहमद अब तक नहीं उठाई गई है। अध्यक्ष दुली चंद का आरोप है कि इस तरह का खतरनाक खेल दिल्ली नगर निगम में (लाहौरी प्रथा) के नाम से प्रचलित है।जो अब इस खतरनाक प्रथा को पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों की धमाचौकडी के चलते ही पीएनबी में भी धीरे-धीरे लागू हो चुकी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दुली चंद के मुताबिक लाहौरी प्रथा के तहत उच्च जातियों के पीटीएस बैंक में भर्ती किए गए। उनमें से बहुत से कर्मी तो सफाई का काम तक नहीं करते । उन्होंने बाकायदा 2500/- से 3000 रूपये के मेहनताने पर एससी के लोगों को हायर किया हुआ है,जो बैंक में टॉयलेट, गंदगी आदि का सफाई का काम करते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दुली चंद के मुताबिक जनरल कैटेगरी के भर्ती पीटीएस हाजरी लगाकर अपने घर चले जाते हैं। जनरल कैटेगरी के पीटीएस का कहना है कि हम तो ग्रेजुएट है।हम सफाई के लिए नहीं लगे हैं।हम तो प्रमोशन लेकर क्लर्क बनने के लिए भर्ती किए गए हैं। अध्यक्ष दुली चंद के मुताबिक जबकि अन्य एससी/ एसटी कैटेगरी के पीटीएस जो बाल्मीकि है या गरीब जनरल कैटेगरी से स्वीपर के काम के अलावा काउंटर साफ करते हैं।कम्प्यूटर सफाई समेत चपरासी के काम के तहत पानी पिलाने ,चाय बनाने के अलावा झूठे बर्तन साफ करवाने का काम भी लिया जाता है।इंसानी मजबूरी का बैंक मेनेजमेंट पूरा फायदा उठाते हैं।इनसे सांय 5 बजे तक 1/3 के मेहनताने में काम लिया जाता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दुली चंद ने बैंक मेनेजमेंट को इस तरह की(लाहौरी प्रथा) के तहत स्वीपर/पीटीएस का काम लिए जाने की बावत पीएनबी बैंक का नाम बदलकर पीएनबी नगर निगम कर देने की सलाह तक दे डाली। अध्यक्ष दुली चंद ने बताया कि बैंक ने पिछले 25 सालों से (पीटीएस) टेम्परेरी काम करने वालों को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया।जबकि 90 से ज्यादा रिक्तियां पीटीएस के पद पेंडिंग हैं। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक मैनेजमेंट समेत उच्चाधिकारियों को चेताया कि बैंक को बैंक ही रहने दो दिल्ली नगर निगम ना बनने दिया जाए। इस बावत पीएनबी द्वारका के डीजीएम (एचओ) मुकेश सिन्हा से इस संवाददाता ने मोबाइल पर बैंक का पक्ष रखने के लिए संपर्क किया गया ,तो उन्होंने तपाक से कहा कि बैंक द्वारा पूरे रूल के मुताबिक पदों को भरा गया है। उन्होंने माना कि एटीएस के पद के लिए जर्नल कैटेगरी से भी भर्तियां की गई है।

महाराष्ट्र-पश्चिम बंगाल में लू की आशंका, दिल्ली में भी अधिक रहेगा तापमान; आईएमडी ने दी सलाह

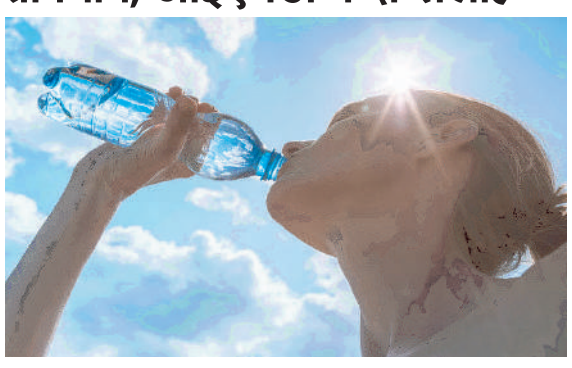

आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि लू से बचने के लिए लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सूती कपड़े पहने और धूप में निकलते वक्त सिर जरूर ढंके।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के कई इलाकों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़ और मुंबई के कई हिस्सों में 27 से 29 अप्रैल तक लू की आशंका जताई है। वहीं, आईएमडी ने कहा कि शनिवार को दिल्ली का अधितम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा, विभाग ने बताया कि लू कम से कम 30 अप्रैल तक दक्षिणी पश्चिम बंगाल में सामान्य जीवन को प्रभावित करेगा। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि लंबे समय तक धूप से रहने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सूती कपड़े पहने और धूप में निकलते वक्त सिर जरूर ढंके।

दिल्ली का तापमान 40 डिग्री रहने का आशंका

आईएमडी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग की मानें तो शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशंका है। हालांकि, विभाग का अनुमान है कि दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हवाएं चलेंगी।

महाराष्ट्र में लू से बचने की सलाह

आईएमडी ने महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़ और मुंबई के कई हिस्सों में 27 से 29 अप्रैल तक लू की आशंका जताई है। ठाणे, रायगढ़ और मुंबई के कई हिस्सों में एक गैर-चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिस वजह से तापमान में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि 27 और 28 अप्रैल को तापमान काफी अधिक रह सकता है। मुंबई सहित आस पास के इलाकों में जारी यह लू का दूसरा अलर्ट है।

नबीन सरकार को फीकी दीजिये : अमित शाह

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वरः बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है । उन्होंने सीधे तौर पर नवीन पटनायक की आलोचना की और कहा कि यह सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त है ।खनन की खुली लूट चल रही है। देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा ओडिशा में है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी ओडिशा में है।20 साल से जो भी विकास हुआ, वो अब एसि भी है । श्री शाह ने ओडिशा की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि नवीन पटनायक को 25 साल तक शासन करने का मौका दिया है । अगर सिर्फ 5 साल बीजेपी को मिल जाएं तो ओडिशा को देश का नंबर वन राज्य बना देंगे ।

बिजेड़ी दल की बरिस्ट नेता श्री नगेंद्र प्रधान कोंग्रेस मे शामिल

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : पूर्व मंत्री और पूर्व लोकसभा सांसद बिजेड़ी नेता श्री नगेंद्र प्रधान कोंग्रेस मे शामिल हुए ।कोंग्रस प्रभारी अजय कुमार , प्रसाद हरिचंदन , भक्त चरण दास और बिस्वरंजन महाती की उपस्थिति से कोंग्रेस पार्टी में शामिल हुए । प्रभारी अजय कुमार ने कहा नगेंद्र बाबू कोंग्रेस मे शामिल होने से सारे राज्य मे इनका प्रभाब पड़ेगा ।सम्बलपुर लोकसभा खेत्र से 2014 से 2019 संसद थे और सिख्या मंत्री थे ।2019 में बिजेड़ी उनको टिकेट मिला नहीं ।सायद सम्बलपुर सांसद केलिए कोंग्रेस टिकेट से लड़ सकते हैं ।सम्बलपुर लोकासभा सीट एक हट सीट कन्यू की इसी सीट पर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हैवी वेट बिजेड़ी नेता प्रणब प्रकाश दास चुनाब लड़ रहे हैं । नगेंद्र प्रधान चुनाब लड़ेंगे तो ये नागेंद्र प्रधान जीत सकते हैं कन्यू की ये दोनो संसदीय खेत्र बहार का लोगों है ।यहाँ की सांसद रहे चुके है और उनकी तजुर्बा भी ज्यादा है ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023